वर्ष-10//अंक-1//अक्टूबर 2022

ISSN 2454–5805

₹20/-

आम आदमी पत्रिका®

एक आम इंसान की सोच

RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात

छत्तीसगढ़ मे अस्तित्व में आए 3 नए जिले

» 6

खिलखिला उठा मुस्कान का चेहरा

» 12

गोधन न्याय योजना से धरती माता की सेवा

» 20

आम जनता को योजनाओं का लाभ देकर उन्हें बढ़ाना प्राथमिकता

SWITCH TO ORGANIC

Because Immunity Is What You Eat

ORGALIFE®

ORGANIC STORE

All Product Range Available At Orgalife Exclusive Store

OPP. SHRI RAM MANDIR, SHOP No.15, VIP CHOWK, RAIPUR (C.G.)

For Trade Queries/Suggestions +91-9755188822 care@orgalife.in www.orgalife.in Follow us on

आम आदमी पत्रिका

वर्ष-10//अंक-1//अक्टूबर 2022

प्रबंध संपादक : उमेश के बंसी

सर्कुलेशन इंचार्ज : प्रकाश बंसी

रिपोर्टर : नेहा श्रीवास्तव

कंटेंट राईटर : प्रशांत पारीक

क्रिएटिव डिजाइनर : देवेन्द्र देवांगन

मैग्जीन डिज़ाइनर : युनिक ग्राफिक्स

मार्केटिंग मैनेजर : किरण नायक

एडमिनिस्ट्रेशन : निरूपमा मिश्रा

अकाउंट असिस्टेंट : प्रियंका सिंह

ऑफिस कॉर्डिनेटर : योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय

965/1 कक्कड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब,रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन : 0771-4044047

ईल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम.
रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर
(छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका

अक्टूबर 2022

इस अंक में

पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 21 साल से सत्ता में बने हुए हैं. पहले गुजरात के मुख्यमंत्री फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उनकी जो पारी शुरू हुई उसने इतिहास रच दिया.

5

अब बदल रहा है छत्तीसगढ़

8

सीएम बघेल के नेतृत्व में बदलाव की बयार देखने को मिल रही है.

आखिर कौन हैं ये हाटी समुदाय

10

मंत्रिमंडल ने एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी.

महारानी एलिजाबेथ के धर्म पर बवाल

12

क्या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ मुस्लिम थीं ?

खेतों में पहुंचा 15 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट

22

राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में दो इंडस्ट्रीयल पार्क...

मलेरिया की दवाई बेचने वाली कंपनी

28

कई कंपनियां ऐसी हैं, जिनके नाम से प्रोडक्ट को जाना जाता है

बाढ़ और सूखा प्रकृति का हिस्सा हैं

32

भारत में बाढ़ से कर्नाटक, तमिलनाडु व तेलंगाना पस्त है.

शिव सेना पर शिकंजे की सियासत!

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

अभी कई राज्यों की राजनीति करवट ले रही है, लेकिन लोगों की नजर महाराष्ट्र पर सबसे अधिक है. यहां की राजनीति में उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही, जो पिछले दिनों तब शुरू हुई थी, जब शिव सेना दो हिस्सों में बंट गई थी. उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, दोनों गुटों में खुद को असली शिव सेना बताने की होड़ है. इसके लिए वे कभी चुनाव आयोग के पास जाते हैं, कभी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो कभी शक्ति प्रदर्शन का सहारा लेते हैं. दशहरा के दिन दोनों गुटों की अलग-अलग जनसभा शक्ति प्रदर्शन की एक और कवायद थी.

यह सच है कि कौन शिव सेना असली है और कौन टूटा हुआ धड़ा, इसका फैसला जनता के बीच किए गए शक्ति प्रदर्शन से नहीं होगा. यह निर्णय तो नियमों अथवा कानूनी तौर-तरीकों से होगा. अदालत या चुनाव आयोग इस बाबत फैसला करेगा. मगर शक्ति प्रदर्शन से शिव सेना के ये दोनों गुट अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं. बगावत के बाद शिंदे खेमे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद हासिल किया. लिहाजा, वह इसे आसानी से नहीं गंवाना चाहते. जबकि, उद्धव ठाकरे अपने परिवार द्वारा स्थापित पार्टी को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं हैं. जहां शिंदे खेमे के पास सरकार में बने रहने और खुद को असली शिव सेना की मान्यता दिलाने की चुनौतियां हैं, वहीं उद्धव ठाकरे के पास पार्टी को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी है.

टूट के समय कई विधायक बेशक शिंदे खेमे में चले गए और उन्होंने सरकार भी बना ली, परंतु संगठन का बड़ा हिस्सा आज भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा दिखाई देता है. कम से कम जनसभा में उमड़ी भीड़ और पार्टी कार्यकताओं का उत्साह देखकर फिलहाल यही प्रतीत होता है. आखिर अपने गुट को असली शिव सेना साबित करना महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों जरूरी है और इसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा?

दरअसल, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र (48 निर्वाचन क्षेत्र) में ही हैं. यह भले कहा जाता रहा हो कि अगर किसी पार्टी को केंद्र की सत्ता चाहिए, तो उसको उत्तर प्रदेश में जीतना होगा, लेकिन संख्या बल के नजरिये से महाराष्ट्र का महत्व भी कुछ कम नहीं है. कुछ पिछली केंद्र सरकारों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजनीति में क्यों महत्व रखता है?

इसमें शिव सेना कहां ठहरती है? साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में जहां प्रतिकूल हवा के बावजूद उसने क्रमश 12 और 11 सीटों पर अपना दबदबा कायम किया, वहीं 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उसने 18-18 सीटें अपने नाम कीं. एक आम सोच यह भी है कि महाराष्ट्र में शिव सेना बडे.भाई की भूमिका निभाती रही है, जबकि भाजपा छोटे भाई की. मगर तथ्य इस धारणा को खारिज करते हैं. लोकसभा चुनावों के ही आंकड़े बताते हैं कि 2004 में महाराष्ट्र में शिव सेना को जहां 12 सीटें मिलीं, तो भाजपा को 13 मिली थीं. साल 2009 के चुनाव में शिव सेना ने 11, तो भाजपा ने नौ सीटें जीतीं. साल 2014 और 2019 के चुनावों में शिव सेना ने 18-18, तो भाजपा को 23-23 सीटें मिलीं. बेशक कुछ विधानसभा चुनावों में शिव सेना गठबंधन में बड़ी पार्टी समझी गई होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव इसकी तस्दीक नहीं करते.

महाराष्ट्र की राजनीति की एक सच्चाई यह भी है कि यहां बहुकोणीय मुकाबला होता रहा है. शिव सेना, भाजपा, कांग्रेस या एनसीपी, किसी भी पार्टी के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने दम पर दूसरों का सामना कर सके. ऐसे में, जब कुछ पार्टियों का गठबंधन बन जाए, तो किसी भी दल के लिए यहां अकेले चुनाव लड़ना आसान नहीं रहता. भाजपा ने यहां हमेशा शिव सेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है. उसे 2024 में सहयोगी दल की सख्त जरूरत होगी. मौजूदा हालात यही बताते हैं कि उसका शिंदे खेमे के साथ गठबंधन होगा, जबकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे. इसका ट्रेलर अभी हम बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनावों में देख सकेंगे, जिसमें पता चल सकेगा कि गठबंधन की आखिर क्या स्थिति बनेगी?

ये हैं वो 7 नारे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया ब्रांड मोदी

नई दिल्ली. पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में पूरे 72 साल के हो गए. लगातार पिछले 21 साल से सत्ता में बने हुए हैं. पहले गुजरात के मुख्यमंत्री फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर. 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उनकी जो पारी शुरू हुई उसने इतिहास रच दिया. 2014 के चुनाव प्रचार से लेकर अब तक उन्होंने और भाजपा जो भी नारे दिए वो लोगों की जुबान पर चढ़ गए.

इस खास अवसर पर जानिए, ऐसे ही कुछ नारों के बारे जो सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान तक छाए रहे और पीएम मोदी की सकारात्मक छवि बनाईङ्क

अच्छे दिन आने वाले हैंः इस नारे की शुरूआत 2014 में हुई. आम चुनाव के प्रचार के दौरान यूपीए-2 की कथित महंगाई, भ्रष्टाचार और नाकामियों पर वार करते हुए पीएम मोदी ने यह नारा दिया था. लोगों को चुनाव के बाद इन दोनों समस्याओं से मुक्ति दिलाने का वादा दिया था. नतीजा, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी.

अबकी बार, मोदी सरकारः 2014 में भाजपा ने जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था तो चुनावी अभियान का नारा दिया गया था- अबकी बार- मोदी सरकार. यह नारा लोगों की जुबान पर चढा और पार्टी के पक्ष में लहर बन गई.

हर-हर मोदी, घर-घर मोदीः लोकसभा चुनाव 2014 के प्रचार के दौरान पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे थे. प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है. इसी प्रचार के दौरान उनके समर्थन में हर तरफ नारे लगे थे, हर-हर मोदी, घर-घर मोदी.

मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्डः भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रण लेते हुए पीएम मोदी ने दुनियाभर की दिग्गज कंपनियों को भारत आने, निवेश करने और कारोबार करने का इंविटेशन दिया था. उन्होंने कंपनियों से यहां आकर प्रोडक्ट को बनाने और उसे दुनियाभर के बाजार में बेचने की गुजारिश की थी. इसी क्रम में उन्होंने मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया.

सबका साथ, सबका विकासः पीएम नरेंद मोदी ने अपने कार्यकाल में कई विकास योजनाओं की नींव रखीं. विकास योजनाओं को देश की जनता को सौंपते हुए नारा दिया- सबका साथ-सबका विकास. इस नारे के जरिए देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की प्राथमिकता तय की.

मैं भी चौकीदारः जिस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में कई नारे चर्चा में रहे उसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी एक ऐसा ही नारा चर्चा में आया. पीएम मोदी ने सभा के दौरान कहा, किसी को देश के संसाधनों की चोरी नहीं करने देंगे. उन्होंने खुद को देश का चौकीदार बताया. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बायो मैं भी चौकीदार लगा देखा गया.

वोकल फॉर लोकलः यह पीएम मोदी का ऐसा नारा था जिसने उनकी छवि गढ़ने के साथ स्थानीय स्तर के कलाकारों को रोजगार बढ़ाने में भी मदद की. पीएम मोदी ने 'वोकल फॉर लोकल' का नारा देते हुए कहा कि आज जो दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं वो कभी न कभी एक स्टार्टअप ही रही होंगी.

> रायपुर. मुस्कान को भी क्या मालूम था कि एक दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके घर के आसपास आएंगे और उनका जो सपना है उसे पूरा कर देंगे ? बीएससी गणित की पढ़ाई पूरी करने के बाद रिसर्च करने का ख्वाब संजोए मुस्कान अपने इरादे घर में इसलिए भी जाहिर नहीं कर पाती थी कि पढ़ने और बाहर जाने के लिए लाखों रुपए कहा से आएंगे ?

क्योंकि एक छोटा सा किराना दुकान से घर का खर्च चलता है,फिर छोटे भाई-बहन भी तो है. अपनी ख़्वाहिशों को दबाए हुए मुस्कान खुद भी घरवालों की मदद के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी. आज जब मुस्कान ने सुना कि घर के पास मुख्यमंत्री आने वाले हैं और वे लोगों से मिलते भी हैं तो यह सोचकर चली आई कि पता नहीं मिल पाऊंगी या नहीं, उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं! यहाँ जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुस्कान की व्यथा और इच्छा जानी,सुनी तो मिनटों में उनकी मिन्नतों को पूरा कर दिया.

धरमजयगढ़ की धरा पर भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के जरिए आए प्रदेश के मुख्यमंत्री को छात्रा मुस्कान अग्रवाल ने जब अपनी व्यथा बताई कि वह गरीब परिवार से है और बीएससी की पढ़ाई पूरी कर चुकी है, अब आगे रिसर्च के फील्ड में जाना चाहती है. बैंगलोर में जाकर पढ़ाई करने चाहती है. इसके लिए कोचिंग करना जरूरी है, लेकिन वह सक्षम नहीं है. मुख्यमंत्री ने छात्रा की बातों को ध्यान से सुना और कहा बताओ कितना चाहिए? छात्रा मुस्कान ने स्टीमेट नहीं बनाने की बात बताई तो मुख्यमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि आप एक मुख्यमंत्री से बिना स्टीमेट के बातें

खिलखिला उठा मुस्कान का चेहरा

जब सीएम भूपेश बघेल ने की स्वेच्छा अनुदान से दो लाख देने की घोषणा

कर रहे हो तो मैं कैसे आपको राशि दे पाऊंगा. पल भर के लिए शांत होकर चुप्पी साधने वाली मुस्कान की मुस्कुराहटों को देखकर मुख्यमंत्री ने उन्हें आवेदन देने की बात कहते हुए तुरंत ही स्वेच्छानुदान से दो लाख रुपए देने को घोषणा कर दी. मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर वहाँ उपस्थित महिलाओं सहित लोगों ने तालियां बजाकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया. धरमजयगढ़ की मुस्कान अग्रवाल ने बताया कि वह घर में पैसे की कमी को देखते हुए किसी को अपनी इच्छा बता नहीं पाती थी. कई बार उसने बाहर पढ़ने जाने का प्लान भी बदल दिया था. आज पल भर में मुख्यमंत्री से मुलाकात और मांग पूरी होने पर छात्रा मुस्कान ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए धन्यवाद भी ज्ञापित किया.

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

अब बदल रहा है छत्तीसगढ़ अंदरूनी क्षेत्रों तक हो रही प्रशासन की पहुंच

रायपुर. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बदलाव की बयार देखने को मिल रही है. एक ओर स्वयं मुख्यमंत्री भेंट-मुलाकात अभियान के तहत प्रदेश की ग्रामीण अंचलों में पहुंच रहे हैं. वहीं प्रशासन भी अब प्रदेश के संवेदनशील और अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रहा है.

इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के बड़ेराजपुर विकासखण्ड के अंतिम छोर पर बसे संवेदनशील ग्राम बस्तरबुडरा एवं भालूपानी में जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पहुंचे. यहां जिला कलेक्टर और एसपी ने ग्रामीणों के साथ वक्त बिताया साथ ही उन्हें उपहार दिये.

सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया है. इसे छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य भी बनाया गया है. इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए शासन-प्रशासन निरंतर कार्य भी कर रहा है. इसी कड़ी में बुधवार को कोण्डागांव के बड़ेराजपुर विकासखण्ड के अंतिम छोर पर बसे संवेदनशील ग्राम बस्तरबुडरा एवं भालूपानी में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 'मावा गिरदा कोंडानार' कार्यक्रम में शामिल होने कलेक्टर दीपक सोनी एवं पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल पहुंचे. पहली बार जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को अपने बीच पाकर ग्रामीणों की खुशी देखते बन रही थी. जिला कलेक्टर एवं एसपी ने भी ग्रामीणों की भावनाओं को समझते हुए उनके साथ वक्त बिताया साथ ही स्थानीय युवाओं और स्कूली बच्चों को खेलने के लिए व्हॉलीबॉल, क्रिकेट किट का वितरण करते हुए सभी युवाओं को टी-शर्ट बांटे. वहीं स्कूली बच्चों को चॉकलेट एवं नोटबुक भी गिफ्ट में दिए.

मावा गिरदा कोंडानार के तहत बच्चों को बांटा गिफ्ट

इस अवसर पर कलेक्टर ने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं के संबंध में जाना एवं ग्रामीणों से गांव में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में जानकारी लेते हुए समस्याओं के निदान हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने युवाओं को कहा कि प्रशासन हर कदम में ग्रामीणों के साथ है. उन्होंने गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा मनरेगा द्वारा स्वीकृत कार्यों की संख्या को दोगुना करते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को दिलाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने राजीव मितान क्लब के सदस्यों से भी मुलाकात करते हुए उन्हें ग्राम के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया.

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन लोगों की सहायता हेतु सदैव तत्पर है. मावा गिरदा कोंडानार (मेरा खुशहाल कोण्डागांव) का उद्देश्य विश्वास, विकास एवं सुरक्षा प्रदान करना है. जिसके तहत उन्होंने बच्चों को पुलिस के पास जाने से होने वाले संकोच को दूर करने के लिए शिक्षकों को स्कूली बच्चों को निकटतम थाने में शैक्षणिक भ्रमण कराने को कहा. उन्होंने यहां के युवाओं को पुलिस सेवा, थल सेना, सीमा सुरक्षा बल एवं सीआरपीएफ से जुड़कर देश की सेवा करने को प्रोत्साहित किया.

मोटर साइकिल से कलेक्टर-एसपी पहुंचे भालूपानी, लगाई चौपाल:

इस दौरान कलेक्टर एवं एसपी भालूपानी मार्ग पर सड़क निर्माण के सर्वेक्षण एवं ग्रामीणों से मिलने मोटरसाइकिल में सवार होकर भालूपानी पहुंचे. जहां उन्होंने खाट पर बैठकर चौपाल का आयोजन किया. चौपाल में आये भालूपानी और टपरापानी के ग्रामीणों ने पहली बार अपने बीच कलेक्टर एवं एसपी को पाकर हर्ष व्यक्त किया साथ ही गांव में बिजली, पानी एवं सड़क की समस्या के संबंध में जानकारी दी. जिस पर कलेक्टर द्वारा जल्द से जल्द वन विभाग के माध्यम से सड़क निर्माण, गांव में पेयजल हेतु दो बोर खोदने एवं जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के निर्देश दिए. विद्युत संबंधी समस्या हेतु कलेक्टर ने तुरंत क्षेत्र के उप अभियंता को बुलाकर विद्युत लाइनों के विस्तार हेतु निर्देश दिए.

आखिर कौन हैं ये हाटी समुदाय

st में शामिल होने के बाद हिमाचल में तय करेंगे किसके सिर पर होगा ताज !

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. यह विधेयक हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की पैरवी करता है. मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के कुछ समुदाय को भी एसटी में शामिल किया है.

केंद्र सरकार के इस फैसले को देखकर माना जा रहा है कि इस कदम से आने वाली चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा मिल सकता है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जिस हाटी समुदाय को एसटी में शामिल किया है, वो हैं कौन. साथ ही जानते हैं कि हाटी समुदाय के एसटी में शामिल होने से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है.

चुनाव में कितना होगा असर?

बता दें कि हाटी समुदाय सिरमौर जिले के चार विधानसभा क्षेत्र में रहता है, जिसमें शिलाई, पावटा साहिब, रेणुका और पच्छाद शामिल है. अब इस फैसले से ट्रांस गिरी क्षेत्र की 154 पंचायतों की करीब तीन लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी. अब इन चार सीटों पर बीजेपी को खास फायदा मिलने की उम्मीद है और ये फैसला चुनाव परिणाम में अहम भूमिका निभा सकता है. इन सीटों के अलावा कई जिलों में ये अहम भूमिका है और माना जाता है कि इन जरिए 9 सीटों पर लक्ष्य साधा जा सकता है. दरअसल, अब उनकी करीब 50 साल पुरानी मांग पूरी हुई है.

बता दें कि साल 2009 में पहली बार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान इसे अपने घोषणापत्र में शामिल करके इस मांग को मान्यता दी और वो ऐसा करने वाली पहली पार्टी बनी. कहा जाता है कि इसका पार्टी को फायदा भी मिला और इसके बाद भी कई बार बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया. फिर साल 2014 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिरमौर के नाहन में एक रैली के दौरान हटिस को एसटी का दर्जा देने का वादा किया था. इससे कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला इलाका बीजेपी के पक्ष में आता दिखाई दिया. ऐसे में अब वादा पूरा होने पर बीजेपी इसका फायदा

कौन है हिमाचल प्रदेश के हाटी?

हाटी समुदाय के लोग वो हैं, जो कस्बों में हाट नाम के छोटे बाजारों में सब्जियां, फसल, मांस या ऊन आदि बेचने का परंपरागत काम करते हैं. हाटी समुदाय के पुरुष आम तौर पर एक सफेद टोपी पहनते हैं. ये समुदाय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गिरी और टोंस नदी के बसे हुए हैं और जौनसार बावर क्षेत्र में भी इनका विस्तार है. ये एक वक्त कभी सिरमौर शाही संपत्ति का हिस्सा थे. हिमाचल के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय और उत्तराखंड के जौनसार बावर के जौनसारी समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ ही भौगोलिक समानता भी है. जौनसार बावर क्षेत्र को 1968 में ही जनजाति का दर्जा मिल चुका है. जबकि गिरीपार क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र और भाटी समुदाय को जनजाति समुदाय घोषित करने की मांग तबसे चल रही है. जो लोग हिमाचल में रहे, उन्हें समान दर्जा या लाभ नहीं दिया गया. अब टोपोग्राफी से जुड़ी दिक्कतों की वजह से कामरौ, संगरा और शिलिया क्षेत्रों में रह रहे इस समुदाय के लोग पढ़ाई और रोजगार की दिक्कतों का सामना करते रहते हैं. जिस तरह हरियाणा में खाप होती है, वैसे ही हाटी समुदाय में खुंबली नाम की पारंपरिक परिषद होती है, जो इससे जुड़े मामलों को देखती है. अभी सिरमौर जिले में काफी हाटी समुदाय के लोग रहते हैं.

छत्तीसगढ़ शासन

गोधन न्याय योजना से गौ माता के साथ धरती माता की कर रहे सेवा

किसानों के लिए रासायनिक उर्वरकों का बेहतर विकल्प है वर्मी कम्पोस्ट- सीएम बघेल

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की 51वीं किश्त की राशि 5 करोड़ 9 लाख रूपए हितग्राहियों को उनके बैंक खाते में अंतरित कर दी है. जिसमें गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 69 लाख रूपए, गौठान समितियों को एक करोड़ 48 लाख रूपए तथा महिला समूहों को 93 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय गए गोबर से निर्मित 15 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का किसान भाईयों ने अपने खेतों में उपयोग किया है. इस योजना के माध्यम से हम गौ माता की सेवा के साथ-साथ धरती माता की भी सेवा कर रहे है. खेतों में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग वास्तव में धरती माता की सेवा है.

गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5.09 करोड़ रूपए की राशि जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से खेतों की मिट्टी मुलायम और उपजाऊ हो रही है. जिन खेतों में वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किसान भाईयों ने अच्छे से किया है, वहां अब अन्य प्रकार के रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 26 लाख से अधिक किसानों को वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध कराने के लिए इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है. इसके लिए उन्होंने गौठानों में बिना किसी व्यवधान के गोबर की नियमित खरीदी करने तथा आवश्यकतानुसार वर्मी टांकों का निर्माण कराए जाने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू खरीफ सीजन में अब तक राज्य के पौने चार लाख किसानों ने फसल ऋण के रूप में सहकारी समितियों से वर्मी कम्पोस्ट का उठाव किया है, यह उत्साहजनक है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी की शुरूआती दौर में कतिपय लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था. आज यह योजना गांवों में लोकप्रिय हो चुकी है. इस योजना की देशभर में सराहना हो रही है. दो सालों के भीतर ही इस योजना के माध्यम से एकसाथ कई लक्ष्यों को साधने के साथ ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान और गोधन न्याय योजना के समन्वय से गांवों में रोजगार के नये अवसर सृजित हुए हैं. राज्य के 5863 गौठान समितियों के बैंक खाते में आज की स्थिति में 79 करोड़ 60 लाख रूपए जमा है. लगभग 2500 गौठान समितियां के पास एक लाख से 10 लाख रूपए तक 46 गौठान समितियों के पास 10 लाख से लेकर 50 लाख रूपए तक स्वयं की पूंजी जमा है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम सुराज और स्वावलंबी गांव के सपने को साकार करने की ओर मजबूत कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि गौठानों में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक पार्क से कई युवा उद्यमी जुड़ना चाहते हैं. हमें उन्हें अवसर देना चाहिए इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगी, लोगों की आय में वृद्धि होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों मे संचालित आयमूलक गतिविधियों और लघु वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण से लोगों की आमदनी बढ़ी है. उनमें खुशहाली आई है. हमें इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की जरूरत है. गौठानों में अब तक 160 करोड़ रूपए की गोबर खरीदी हो चुकी है. गौठानों से जुड़ी समूह की महिला बहनों ने वर्मी कम्पोस्ट और कृषि से जुड़ी गतिविधियों का संचालन कर 80 करोड़ रूपए की आय हासिल की है. गौठानों में आयमूलक गतिविधियां बेहतर तरीके से संचालित हो, इसका प्रयास सभी विभागों के समन्वय से किया जा रहा है. गौठानों में आयमूलक गतिविधियों का विस्तार शेड का निर्माण का कार्य प्राथमिकता से कराया जा रहा है. युवा मितान क्लब को भी गौठानों से जोड़ने की पहल शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि गौठान और गोधन न्याय योजना आज की स्थिति में पशुपालकों, महिला समूहों और भूमिहीन परिवारों के आय का जरिया बन गई है.

आखिर क्यों मचा हुआ है महारानी एलिजाबेथ के धर्म पर बवाल

क्या है उनका मुस्लिम धर्म से कनेक्शन?

क्या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ मुस्लिम थीं? 70 साल तक ब्रिटेन में राज करने वाली महारानी पर एक नई बहस शुरू हो गई है. इस बहस की वजह है वो लेटर जिसमें इस बात का जिक्र किया गया. जिस लेटर में यह जानकारी दी गई है उसका कनेक्शन जॉन बर्क नाम के पब्लिकेशन से है. जॉन ने 1826 में ब्रिटेन के शाही परिवार और कुलीन वर्ग की वंशावली को प्रकाशित करने का काम शुरू किया. वंशावली तैयार करने के लिए जॉन ने पुरखों के इतिहास की पर्त दर पर्त खोल कर रख दीं. शुरूआती दौर में वंशावलियों को दिलचस्प कहानियों का संग्रह बताया गया, लेकिन धीरे-धीरे लोगों की इनमें दिलचस्पी बढ़ने लगी. जॉन का पब्लिकेशन सबसे ज्यादा चर्चा में एक लेटर के कारण रहा. एक दिन जॉन के पब्लिकेशन की डायरेक्टर को लेटर मिला. लेटर में लिखा था कि ब्रिटेन के बहुत कम लोगों को पता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की नसों में पैगम्बर मोहम्मद का खून दौड़ रहा है.

क्या-कुछ लिखा था उस लेटर में?

उस लेटर की शुरूआत में कहा गया था कि आतंकियों से खुद से सुरक्षित रखने के लिए शाही परिवार के पैगंबर मुहम्मद के वंशज होने के दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हालांकि, सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं को इस पर गर्व है. 2018 में मोरक्को के एक अखबार में छपी रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि महारानी का पैगम्बर से कनेक्शन रहा है. रिपोर्ट में कहा गया कि महारानी एलिजाबेथ पैगम्बर की बेटी फातिमा की 43वीं पीढ़ीं से ताल्लुक रखती हैं. यानी उनकी वंशज हैं.

महारानी का पैगम्बर के वंश से क्या है कनेक्शन, अब इसे समझ लीजिए

दरअसल मामले का कनेक्शन जायदा नाम की महिला को बताया गया. इसकी पूरी कहानी शुरू होती है स्पेन के शहर सेविले से. एक दौर ऐसा था जब यहां अब्बासी वंश के शासन की शुरूआत हुई. इस वंश के तीसरे राजा थे मोहम्मद इब्न अब्बास. 1069 से लेकर 1091 तक इनका शासन चला. इन्हें पैगम्बर मोहम्मद की बेटी फातिमा का वंशज बताया गया.मोहम्मद इब्न अब्बास की एक बेटी थी नाम था जायदा. एक ऐसा दौर भी आया जब अब्बासी साम्राज्य पर मोरक्को के अल्मोराविदो शासकों आक्रमण किया. हालात इतने बिगड़ गए कि जायदा को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा. वह अल्फांसो षष्ठम के पास शरण लेने पहुंचीं. लियोन, कैसिले और गेलिसिया की सत्ता के शासक अल्फांसो षष्ठम ने जायदा को अपना लिया. इसके लिए जायदा को अपना धर्म बदलकर ईसाई बनना पड़ा. इतिहासकार और बिशप पेलागियस ओविदो का कहना है कि जायदा अल्फांसो षष्ठम की उप-पत्नी बन गई थीं. दोनों की एक संतान हुई जिसका नाम रखा गया सांचो. सांचो के ही वंशज का इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय के परिवार में विवाह हुआ और उसी वंश से ही एलिजाबेथ पैदा हुईं. इन तरह महारानी के वंश का कनेक्शन अब्बासी वंश से जोड़ा गया.

जायदा से जुड़ी एक कहानी यह भी है

इतिहास में जायदा से जुड़ी एक कहानी और भी बताई गई है. मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक, वह अब्बासी वंश की बहू थीं. जिनकी शादी अल मोहम्मद इब्न अब्बास के बेटे अबु अल फतह से की गई थी. अल्मोराविदो के हमले में पति की मौत वो शरण लेने अल्फांसो के पास पहुंची थीं.

क्या हुआ जब दुनिया में यह बात फैली?

इतिहासकार डेविड स्टारकी के अनुसार, जायदा की मौजूदगी में स्पेन के शाही परिवार और इस्लामिक हुकूमत के बीच काफी घनिष्ट सम्बंध रहे हैं. महारानी एलिजाबेथ और पैगम्बर मोहम्मद के वंश के कनेक्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

जब मोरक्को के अखबार में यह खबर पब्लिश हुई तो हंगामा मच गया. कुछ लोगों को खुशी हुई और कुछ ने आश्चर्य जताया. खुशी जाहिर करने वाले लोगों का कहना था, ब्रिटेन के शाही परिवार में मुस्लिमों का रक्त है. वहीं, नाराजगी जताने वालों लोगों ने कहा कि मुस्लिम समाज अब इन खबरों के जरिए ब्रिटेन में पैठ बनाना चाहता है.

क्वीन ElizÔbeth से जुड़े 10 अनसुने फैक्ट्स, महारानी के पास नहीं था पासपोर्ट, बिना वीजा करती थीं दुनियाभर में ट्रैवल - britÔi»»f quee»»f elizÔbeth pÔssed u»»fk»»fow»»f facts ...

दुनिया भर में कृत्रिम मीट बनाने की मची है होड़... मगर जर्मनी की क्लीन मीट है सबसे अलग

दुनिया भर की कई लैब में कृत्रिम तरीके से मीट यानी मांस को बनाने की कोशिशें जारी हैं. ऐसी ही तैयारी जर्मनी में भी चल रही है. जीव विज्ञानी और रॉयटलिंगन यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता पेट्रा क्लूगर टीम के साथ मिलकर लैब में मीट बना रही हैं. जिसे क्लीनमीट कहा जा रहा है. इसे बनाने की तैयारी 2019 से शुरू हुई थी. वह कहती हैं, इसे तैयार करना समय की जरूरत है.

जर्मनी में तैयार हो रही मीट कुछ मायनों में अलग है. जैसे- इसमें विटामिन-डी समेत कई तरह के पोषक तत्वों को मिलाया जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्लीनमीट कितनी अलग है और दुनियाभर के वैज्ञानिक आखिर कृत्रिम मीट को तैयार करने में क्यों जुटे हुए है? जानिए, इन सवालों के जवाबङ्क

क्या है क्लीनमीट और इसे कैसे तैयार किया जा रहा है?

क्लीनमीट को तैयार करने के लिए असली मांस के बेहद छोटे से टुकड़े की जरूरत होती है. इस छोटे से टुकड़े से मूल कोशिका यानी स्टेम सेल को अलग करते हैं. इसके बाद लैब में बायोलॉजिकल प्रक्रिया के जरिए इन कोशिकाओं की संख्या में कई गुना वृद्धि कराई जाती है ताकि कृत्रिम मीट तैयार किया जा सके. इसे ही क्लीनमीट का नाम दिया गया है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यह मीट तैयार करने का साफसुथरा तरीका है. DW की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में रिसर्च करने वाले 80 से ज्यादा समूह मीट बनाने पर काम कर रहे हैं. 2013 में पहली बार इसे तैयार करने वाली कंपनी मोसामीट ने कृत्रिम मीट से बना पहला बर्गर पेश किया था, जिसकी कीमत थी डेढ़ करोड़ रुपये.

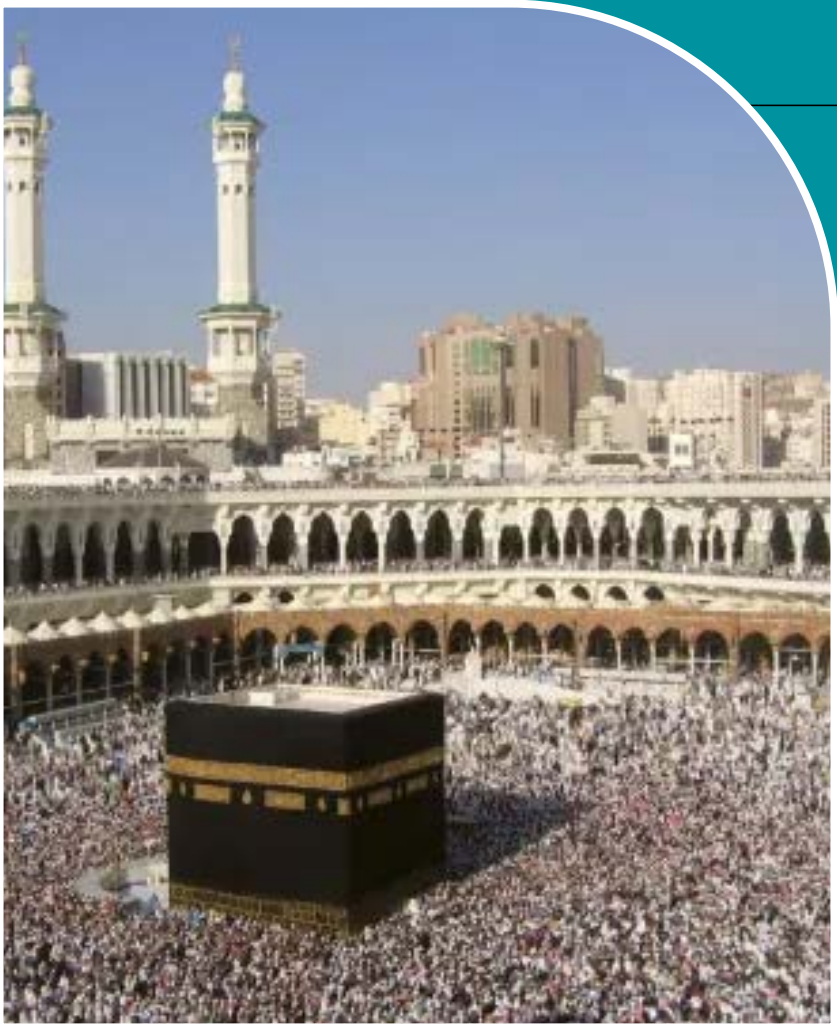

लैब में मांस तैयार की जरूरत क्यों पड़ रही है?

2019 से क्लीनमीट प्रोजेक्ट पर काम कर रहीं पेट्रा क्लूगर कहती हैं, वर्तमान में जो हालात हैं उससे साफ है कि आने वाले 20 सालों में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा. ऐसे में लैब में तैयार होने वाला मीट एक जरूरी भोजन होगा. पेट्रा कहती हैं, लैब में मीट तैयार करने के लिए इसकी प्रक्रिया को और भी आसान और मीट को सस्ता तैयार करने की जरूरत है.

पेट्रा और उनकी टीम लैब में अलग तरह से मीट बनाने की कोशिश कर रही है. वो हजारों कोशिकाओं से स्टेरॉयड्स विकसित कर रहे हैं. वह कहती है, अगर यह आइडिया पूरी तरह सफल हो जाता है तो हम बड़े स्तर पर इसका उत्पादन कर सकेंगे.

लैब में बनी मीट के लिए लोग उत्साहित हैं या नहीं?

लैब में तैयार मीट को ज्यादातर लोग शक की निगाह से देखते हैं. कृत्रिम मीट पर हुआ हालिया सर्वे कहता है कि मात्र 14 फीसदी लोग ही इसे खाना पसंद करेंगे. इसमें भी सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है क्योंकि उनके लिए लैब में बना मीट एक साइंस फिक्शन की कहानी का हिस्सा जैसा है. लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए इजरायल का स्टार्टअप सुपरमीट लम्बे समय से काम कर रहा है. यह स्टार्टअप रेस्तरां में जाकर कृत्रिम मांस से तैयार हुए बर्गर के लिए पार्टी को ऑर्गेनाइज कराता है. इस तरह लोगों को लैब में बने मीट से तैयार व्यंजन को चखने का मौका मिलता है.

क्लीनमीट कैसे अलग है?

पेट्रा कहती हैं, हम अपने तरीके से जो मीट तैयार कर रहे हैं उसे लोगों की जरूरत के मुताबिक बदला जा सकेगा. जैसे- गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसा मीट तैयार हो सकेगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड हो. या फिर बुजुर्गों के लिए विटामिन-डी और आसानी से चबाया जाने वाला मीट भी तैयार किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात

छत्तीसगढ़ में अस्तित्व में आए 3 नए जिले

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नवगठित तीन जिलों के शुभारंभ के साथ अब 31 जिले हो गए हैं। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 सितम्बर को 29 वें जिले मोहला-मानपुर-चौकी और 3 सितम्बर को दो और नए जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़ और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के शुभारंभ करने के साथ तीन नए जिले अस्तित्व में आ गए। इसके साथ ही सारंगढ़-बिलाईगढ़ राज्य का 30 वां और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 31वां जिला बन गया। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि दो दिनों के अंतराल में तीन नये जिलों की सौगात जनता को मिली है।

सनवगठित जिलों के शुभारंभ अवसर पर क्षेत्रवासियों के चेहरे पर अपनी बरसों पुरानी मांग के पूरा होने का उत्साह और हर्ष दिखाई दिया। इन नये जिलों के बन जाने से शासन-प्रशासन की लोगों तक पहुंच और मजबूत होगी, जिससे इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को तीव्र गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने एवं आम जनता को सहूलियत पहुंचाने के उद्देश्य से नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। अब जिलों के शुभारंभ के साथ ही मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद से इन क्षेत्रों के निवासियों की बरसों पुरानी मांग और सपने को साकार कर दिया है।

नवगठित जिलों के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही लोगों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर भव्य अभिनंदन किया और जिला निर्माण के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री के स्वागत में युवाओं ने बाइक रैली निकाली और स्कूली बच्चों ने लोकनृत्य किया। मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान उनके स्वागत में सड़क के दोनों ओर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री को पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनो और फलों से भी तौला गया। मुख्यमंत्री ने नये जिलों के शुभारंभ पर जिलावासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नये जिले के गठन के निर्णय से अभूतपूर्व खुशी दिखी। उन्होंने कहा कि रोड शो में जो भीड़ दिखी, उससे स्पष्ट है कि लोगों के लाभ के लिए कितना बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि 'छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में नवा जिला जुड़ गे हे'। लोगों की मुश्किल कम हो गई।

मुख्यमंत्री बघेल ने मोहला, सारंगढ़ और खैरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवगठित जिलों के शुभारंभ के साथ क्षेत्रवासियों को 1037।37 करोड़ रूपए के कई विकास कार्यों की सौगात दी। बघेल ने मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 106 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया, वहीं सारंगढ़ और खैरागढ़ में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए 931 करोड़ 37 लाख रूपए की सौगात दी। उन्होंने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शुभारंभ अवसर पर 512।29 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 54।52 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के शुभारंभ कार्यक्रम में 364 करोड़ 56 लाख रूपए के विकास कार्यों की सौगात के साथ ही 213 हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 37 लाख 48 हजार रूपए की सामग्री एवं अनुदान सहायता राशि प्रदान की।

नवगठित जिले

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नये प्रशासनिक इकाई के रूप में पहचान बनाने जा रहा है। इस जिले की भौगोलिक सीमाएं उत्तर में जिला राजनांदगांव के तहसील छुरिया, दक्षिण में तहसील दुर्गकोंदल, पखांजुर जिला कांकेर, पूर्व में तहसील डौंडी, डौंडी लोहारा जिला बालोद एवं पश्चित में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है। नवीन जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। नवीन गठित इस जिले में तहसीलों की संख्या 3 है जिसमें अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। विकासखण्ड एवं जनपद पंचायत-अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है।

नवीन जिले में कुल ग्रामों की संख्या 499 है। भौगोलिक क्षेत्रफल 2 लाख 14 हजार 667 हेक्टयर है। यहां कि कुल जनसंख्या 2 लाख 83 हजार 947 है जिसमें अनुसुचित जनजाति की कुल जनसंख्या 1 लाख 79 हजार 662 जो जिले कि कुल जनसंख्या का 63।27 प्रतिशत है। जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या 13 है, कुल पटवारी हल्का नम्बर 89 है, ग्राम पंचायत की संख्या 185 है। जिला मोहला-मानुपर-चौकी में थानों की कुल संख्या 9 है। विधानसभा क्षेत्र 2 तथा कुल मतदान केन्द्र संख्या 497 है। राजनांदगांव जिले से अम्बागढ़ चौकी की दूरी 50 किलो मीटर, मोहला की दूरी 75 किलो मीटर, मानपुर की दूरी 100 किलो मीटर है। यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। नया जिला बन जाने से शासन-प्रशासन इन क्षेत्रों में और निकट तक पहुंचेगा और विकास कार्यों की गति बढ़ेगी। यह क्षेत्र प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है। यहां के सघन वनों में लघुवनोपज प्रचुर मात्रा में है। मोहला-मानपुर क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है।

नवगठित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ का जिला मुख्यालय सारंगढ़, रायगढ़ से रायपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक 200 पर स्थित है। यहां रियासत कालीन समय से हवाई पट्टी स्थित है। जिला मुख्यालय सारंगढ़ छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व से तहसील मुख्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

मुख्यालय है। ज्ञात हो कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिला रायगढ़ के उपखण्ड सारंगढ़, तहसील सारंगढ़ एवं बरमकेला तथा रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के उपखण्ड-बिलाईगढ़ तथा तहसील बिलाईगढ़ को शामिल करते हुए नये जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़ का गठन किया गया है, इसमें तीन तहसील सारंगढ़, बरमकेला एवं बिलाईगढ़ एवं उपतहसील कोसीर तथा भटगांव शामिल होंगे। नवगठित जिले में तीन जनपद पंचायत सारंगढ़, बरमकेला और बिलाईगढ़ शामिल हैं। इस नवगठित जिले की सीमाएं उत्तर में रायगढ़, दक्षिण में महासमुंद जिले तथा पूर्व में ओडिशा के बरगढ़ और पश्चिम में बलौदा बाजार तथा उत्तर-पश्चिम में जांजगीर-चाम्पा जिले से लगी हुई है। नवगठित जिले में रामनामी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। महानदी सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की मुख्य नदी है। वहीं जिले के सारंगढ़-तहसील में स्थित गोमर्डा अभ्यारण्य सैलानियों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सारंगढ़ का दशहरा-उत्सव बस्तर-दशहरा की भांति बहुत प्रसिद्ध है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां की कुल जनसंख्या 6 लाख 17 हजार 252 है। यहां 759 ग्राम, 349 ग्राम पंचायत, 5 नगरीय निकाय हैं। इसके अंतर्गत 20 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल है जिनमें सारंगढ़, हरदी, सालर, कोसीर, छिंद, गोड़म, उलखर, बरमकेला, गोबरसिंघा, देवगांव, डोंगरीपाली, सरिया, बिलाईगढ़, पवनी, गोविंदवन, जमगहन, भटगांव, गिरसा, बिलासपुर एवं सरसीवा शामिल है। इसका कुल राजस्व क्षेत्रफल 1 लाख 65 हजार 14 है एवं 2,518 राजस्व प्रकरण की संख्या है। वर्तमान में नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1,406 स्कूल, 7 कालेज, 33 बैंक, 3 परियोजना, 141 स्वास्थ्य केन्द्र, 10 थाना एवं 2 चौकी स्थापित हैं।

नवगठित खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई दुर्ग संभाग के अंतर्गत इसकी जनसंख्या 3 लाख 68 हजार 444 है। कुल ग्रामों की संख्या 494 तथा 3 नगरीय निकाय हैं। दो उपखण्ड खैरागढ़ एवं गण्डई-छुईखदान होंगे। तीन तहसील गण्डई, छुईखदान, खैरागढ़ होंगे, वहीं 2 विकासखण्ड छुईखदान एवं खैरागढ़, 16 राजस्व निरीक्षक मंडल होंगे। इस नवीन जिले में 107 पटवारी हल्का, 221 ग्राम पंचायतें है। इस नवीन जिले के उत्तर में कबीरधाम जिला, दक्षिण में तहसील डोंगरगढ़, तहसील राजनांदगांव, पूर्व

में तहसील साजा एवं धमधा और पश्चिम में तहसील लांजी जिला- बालाघाट (मध्यप्रदेश) की सीमाएं लगी है। खनिज और संसाधनों से समृद्धि होने से जिला बनने से यहां औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

नया जिला बन जाने से नागरिकों को काफी राहत मिलेगी और कई महत्वपूर्ण कार्य आसानी से होंगे। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण होने का फायदा आम जनता को मिलेगा। बुनियादी सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्यान्न लोगों तक आसानी से उपलब्ध होगी और सुविधाओं का विस्तार होगा। वहीं शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन दूरस्थ अंचलों तक आसानी होगा। रोड कनेक्टिविटी, पुल-पुलिया के निर्माण से सुदूर वनांचल के क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। नया जिला गढ़ने से आने वाले वर्षों में इसके सुखद परिणाम मिलेंगे।

क्षेत्रवासियों को मिली 1037 करोड़ की सौगात

सीएम भूपेश बघेल ने मोहला, सारंगढ़ और खैरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवगठित जिलों के शुभारंभ के साथ क्षेत्रवासियों को 1037।37 करोड़ रूपए के कई विकास कामों की सौगात दी। सीएम ने मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 106 करोड़ रूपए के विकास कामों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। वहीं, सारंगढ़ और खैरागढ़ में विकास एवं निर्माण कामों के लिए 931 करोड़ 37 लाख रूपए की सौगात दी। उन्होंने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शुभारंभ के मौके पर 512।29 करोड़ के विकास कामों का भूमिपूजन एवं 54।52 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण किया, जबकि खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के शुभारंभ कार्यक्रम में 364 करोड़ 56 लाख रूपए के विकास कामों की सौगात दी। साथ ही 213 हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 37 लाख 48 हजार रूपए की सामग्री एवं अनुदान सहायता राशि प्रदान की।

जानिए मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की क्या है खासियत?

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नये प्रशासनिक इकाई के रूप में पहचान बनाने जा रहा है। इस जिले की भौगोलिक सीमाएं उत्तर में जिला राजनांदगांव के तहसील छुरिया, दक्षिण में तहसील दुर्गकोंदल, पखांजुर जिला कांकेर, पूर्व में तहसील डौंडी, डौंडी लोहारा जिला बालोद एवं पश्चित में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है। नवीन जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी दुर्ग संभाग के तहत होगा। नवीन गठित इस जिले में तहसीलों की संख्या 3 है, जिसमें अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। विकासखण्ड एवं जिला पंचायत झ अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है।

वहीं, नवीन जिले में कुल ग्रामों की संख्या 499 है। भौगोलिक क्षेत्रफल 2 लाख 14 हजार 667 हेक्टयर है। यहां कि कुल जनसंख्या 2 लाख 83 हजार 947 है, जिसमें अनुसुचित जनजाति की कुल जनसंख्या 1 लाख 79 हजार 662 है। जो जिले कि कुल जनसंख्या का 63।27 प्रतिशत है। जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या 13 है। कुल पटवारी हल्का नम्बर 89 है, ग्राम पंचायत की संख्या 185 है। जिला मोहला-मानुपर-चौकी में थानों की कुल संख्या 9 है। विधानसभा क्षेत्र 2 और कुल मतदान केन्द्र संख्या 497 है।

राजनांदगांव जिले से अम्बागढ़ चौकी की दूरी 50 किमी, मोहला की दूरी 75 किमी, मानपुर की दूरी 100 किमी है। यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। नया जिला बन जाने से शासन-प्रशासन इन क्षेत्रों में और निकट तक पहुंचेगा और विकास कामों की गति बढ़ेगी। यह क्षेत्र प्राकृतिक वन संपदा से भरा हुआ है। यहां के सघन वनों में लघुवनोपज प्रचुर मात्रा में है। मोहला-मानपुर क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है।

खैरागढ़ को मिलेगी औद्योगिक विकास को गति

नवगठित खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई दुर्ग संभाग के तहत इसकी जनसंख्या 3 लाख 68 हजार 444 है। कुल गांव की संख्या 494 और 3 नगरीय निकाय हैं। दो उप खण्ड खैरागढ़ एवं गण्डई-छुईखदान होंगे। तीन तहसील गण्डई, छुईखदान, खैरागढ़ होंगे।वहीं, 2 विकासखण्ड छुईखदान एवं खैरागढ़, 16 राजस्व निरीक्षक मंडल होंगे। इस नए जिले में 107 पटवारी हल्का, 221 ग्राम पंचायतें है। इस नवीन जिले के उत्तर में कबीरधाम जिला, दक्षिण में तहसील डोंगरगढ़, तहसील राजनांदगांव, पूर्व में तहसील साजा एवं धमधा और पश्चिम में तहसील लांजी जिला- बालाघाट (मध्यप्रदेश) की सीमाएं लगी है। जहां खनिज और संसाधनों से समृद्धि होने से जिला बनने से यहां औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

सारंगढ़ जिले की क्या विशेषता?

नवगठित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ का जिला मुख्यालय सारंगढ़, रायगढ़ से रायपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग 200 पर स्थित है। यहां रियासत कालीन समय से हवाई पट्टी स्थित है। जिला मुख्यालय सारंगढ़ छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व से तहसील मुख्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुख्यालय है। गौरतलब है कि, बिलासपुर संभाग के तहत आने वाले जिला रायगढ़ के उप खण्ड सारंगढ़, तहसील सारंगढ़ एवं बरमकेला तथा रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के उप खण्ड-बिलाईगढ़ है। वहीं,तहसील बिलाईगढ़ को शामिल करते हुए नए जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़ का गठन किया गया है,जिसमें तीन तहसील सारंगढ़, बरमकेला एवं बिलाईगढ़ एवं उप तहसील कोसीर और भटगांव शामिल होंगे। नवगठित जिले में 3 जिला पंचायत सारंगढ़, बरमकेला व बिलाईगढ़ शामिल हैं। इस नवगठित जिले की सीमाएं उत्तर में रायगढ़, दक्षिण में महासमुंद जिले और पूर्व में उड़ीसा के बरगढ़ और पश्चिम में बलौदा बाजार और उत्तर-पश्चिम में जांजगीर-चाम्पा जिले से लगी हुई है। नवगठित जिले में रामनामी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। महानदी सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की मुख्य नदी है। वहीं जिले के सारंगढ़- तहसील में स्थित गोमर्डा अभ्यारण्य सैलानियों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सारंगढ़ का दशहरा-उत्सव बस्तर-दशहरा की भांति बहुत प्रसिद्ध है।

साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 6 लाख 17 हजार 252 है।759 ग्राम, 349 ग्राम पंचायत, 5 नगरीय निकाय है, जिसके तहत 20 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल है, जिनमें सारंगढ़, हरदी, सालर, कोसीर, छिंद, गोड़म, उलखर, बरमकेला, गोबरसिंघा, देवगांव, डोंगरीपाली, सरिया, बिलाईगढ़, पवनी, गोविंदवन, जमगहन, भटगांव, गिरसा, बिलासपुर एवं सरसीवा शामिल है। जिसका कुल राजस्व क्षेत्रफल 01 लाख 65 हजार 14 है एवं 2518 राजस्व की संख्या है। वर्तमान में नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1406 स्कूल, 7 कालेज, 33 बैंक, 3 परियोजना, 141 स्वास्थ्य केन्द्र, 10 थाना एवं 2 चौकी स्थापित है।

आम जनता को पारदर्शी प्रशासन और योजनाओं

का लाभ देकर उन्हें बढ़ाना प्राथमिकता

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि आम जनता की सेवा ही इस सरकार का प्रमुख उद्देश्य है. आम जनता के समस्याओं का समय पर निराकरण और पारदर्शी प्रशासन के साथ हितग्राहियों की संतुष्टि सभी के प्राथमिकता में होनी चाहिए. यदि किसी की शिकायत आएगी तो मुझे कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा. इसलिए कोई ऐसा कार्य न करे, जिससे कि आपकी शिकायत हो. प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विधानसभा में स्थानीय अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जहाँ भी जा रहे हैं, कलेक्टर और एसपी को आम जनता की समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में निर्देश दे रहे हैं. आम जनता की सेवा, उन्हें सुविधाएं, उनका सम्मान, सुरक्षा और उनकी समृद्धि सभी की प्राथमिकता में होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में गरीब, आदिवासी, पिछड़े निवास करते हैं. वे बहुत ही उम्मीदों के साथ अधिकारियों के पास शासन की योजनाओं का लाभ उठाने या अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जाते हैं. उन्हें बार-बार किसी कार्यालय या अधिकारियों के चक्कर न काटना पड़े, यह सभी सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने धरमजयगढ़ में विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमिपूजन भी किया.

हाथी व मानव द्वंद रोकने जागरूक करें

मुख्यमंत्री ने धरमजयगढ़ क्षेत्र में कुपोषण और एनीमिया दूर करने चलाये जा रहे अभियान की जानकारी ली. उन्होंने गरम भोजन के साथ अन्य पोषण आहार समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने भवनविहीन स्कूलों की जानकारी लेते हुए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने, वन अधिकार पत्र वितरण करने, हाट बाजार क्लीनिक योजना से दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को समय पर उपचार करने, सड़कों को सुधारने, लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने क्षेत्र में हाथी के विचरण और होने वाले नुकसान की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने हाथी मानव द्वंद को रोकने के लिए वनों में नरवा अंतर्गत वन्य जीव के लिए पानी, हाथियों के लिए फलदार वृक्ष लगाने तथा लोगों में जागरूकता लाने के निर्देश दिए. उन्होंने पेसा कानून के विषय में ग्रामीणों को जानकारी देने व जल स्रोत वाले क्षेत्रों में स्टॉप डेम बनाकर आदिवासी क्षेत्रों में सिचाई व्यवस्था के निर्देश भी दिए.

लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाएं इस दिशा में काम करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके क्षेत्र में शिक्षा,स्वास्थ्य में सुधार हो. कोई महिलाएं एनीमिक न हो, कोई बच्चा कुपोषण का शिकार न हो. शासन की योजनाएं उन तक पहुँचे. गौठान मजबूत बने और आर्थिक विकास का जरिया बने. इस दिशा में काम हो. महिला स्व सहायता समूहों से लेकर सभी की आमदनी और समृद्धि बढ़े इसके लिए अधिकारियों को जागरूकता फैलाने काम करना चाहिए. सरकार का भी यहीं उद्देश्य है.

खेतों में पहुंचा 15 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका के केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए वहां महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क बनाया जाएगा. राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में दो इंडस्ट्रीयल पार्क बनेंगे. इसे स्थानीय, शासकीय एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण उत्पादन एवं सेवा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन इंडस्ट्रियल पार्क में निजी उद्यमियों को उद्यम लगाने प्रोत्साहित किया जाएगा. दो अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा. इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज महानदी मंत्रालय भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की बैठक लेकर रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना एवं वहां गतिविधियों के संचालन के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए है. महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अर्थात ग्रामीण आजीविका पार्क योजना के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में दो गौठानों को इंडस्ट्रियल पार्क के लिए चयन किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक रीपा में लिए जाने वाली गतिविधियों हेतु समेकित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा ब्लूप्रिंट तैयार कर प्रत्येक उद्यम हेतु पृथक-पृथक बिजनेस प्लान के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जाये और उद्यम स्थापित करने इच्छुक स्थानीय युवाओं, स्व सहायता समूहों को चिन्हांकित कर लिया जाये. बैठक में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के संबंध में कार्ययोजना के अनुसार कलेक्टर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है. रीपा के क्रियान्वयन के संबंध में प्रत्येक जिले में अब तक की गई कार्यवाही की विस्तार से जानकारी ली गई. राज्य स्तर पर कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण हेतु समय सारणी के अनुसार रायपुर संभाग के सभी जिलों को 19 सितम्बर को, बस्तर संभाग के जिलों को 20 सितम्बर, बिलासपुर संभाग के जिलों को 21 सितम्बर को, दुर्ग संभाग के जिलो को 22 सितम्बर को और सरगुजा संभाग के जिलो को 23 सितम्बर को राज्य स्तर पर प्रस्तुतीकरण देने के निर्देश दिए गए है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मे मिशन संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अवनीश शरण, नोडल अधिकारी गोधन न्याय योजना डॉ. अयाज तम्बोली सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए.

क्या श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी निष्प्रभावी हो सकता है

1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट? जानें पूरा मामला

नई दिल्ली. ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट अहम फैसला सुना चुकी है. कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है. वहीं अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसकी दलील थी कि ज्ञानवापी पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होता है. यानी ज्ञानवापी के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है. अब मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर आगे सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी माना कि इस मामले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता. 1991 का कानून कहता है कि आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था, वो भविष्य में उसी रूप में रहेगा. अब इस फैसले का असर कई और मामलों पर भी पड़ सकता है.

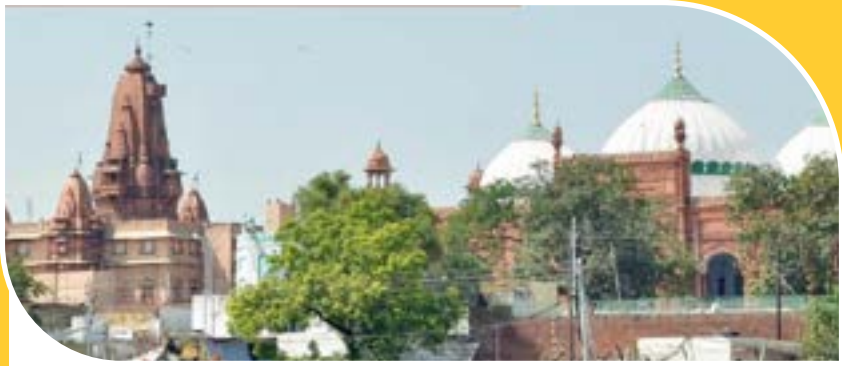

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट?

इस कानून को 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था. इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता. इस कानून में कहा गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है. कानून के मुताबिक आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा.

अब क्या है मामला?

अब जो मामले कोर्ट में गए हुए हैं, वो इसी समझौते के खिलाफ है. याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन आदि की ओर इसी समझौते पर सवाल उठाया गया है. उनका कहना है कि ट्रस्ट को कोई अधिकार ही नहीं था कि वो ऐसा कोई समझौता करे. याचिकाकताओं ने दावा किया है कि इस समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है. हिन्दू पक्ष का दावा है कि उसका इस पूरे 13.37 एकड़ पर अधिकार है जो उसे मिलना चाहिए क्योंकि इसी जमीन पर उनके इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इस जमीन पर उनका ही अधिकार होना चाहिए.

मथुरा विवाद पर क्या असर पड़ेगा?

अयोध्या और काशी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मथुरा के मामले में भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद सुलझ चुका है. वहीं वाराणसी के जिला कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी मामले में भी सुनवाई होगी. कोर्ट ने इस मामले में भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू ना होने की बात कही है. 1991 के कानून से सिर्फ अयोध्या विवाद को छूट मिली थी, क्योंकि वो मामला आजादी से पहले अदालत में था. अब कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में भी इस कानून के दायरे से बाहर माना है. जबकि, मथुरा मामले में पूरी कानूनी लड़ाई 1968 के समझौते से शुरू होती है. ऐसे में यह कोर्ट पर निर्भर करेगा कि क्या वह इस मामले को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से छूट देता है या नहीं.

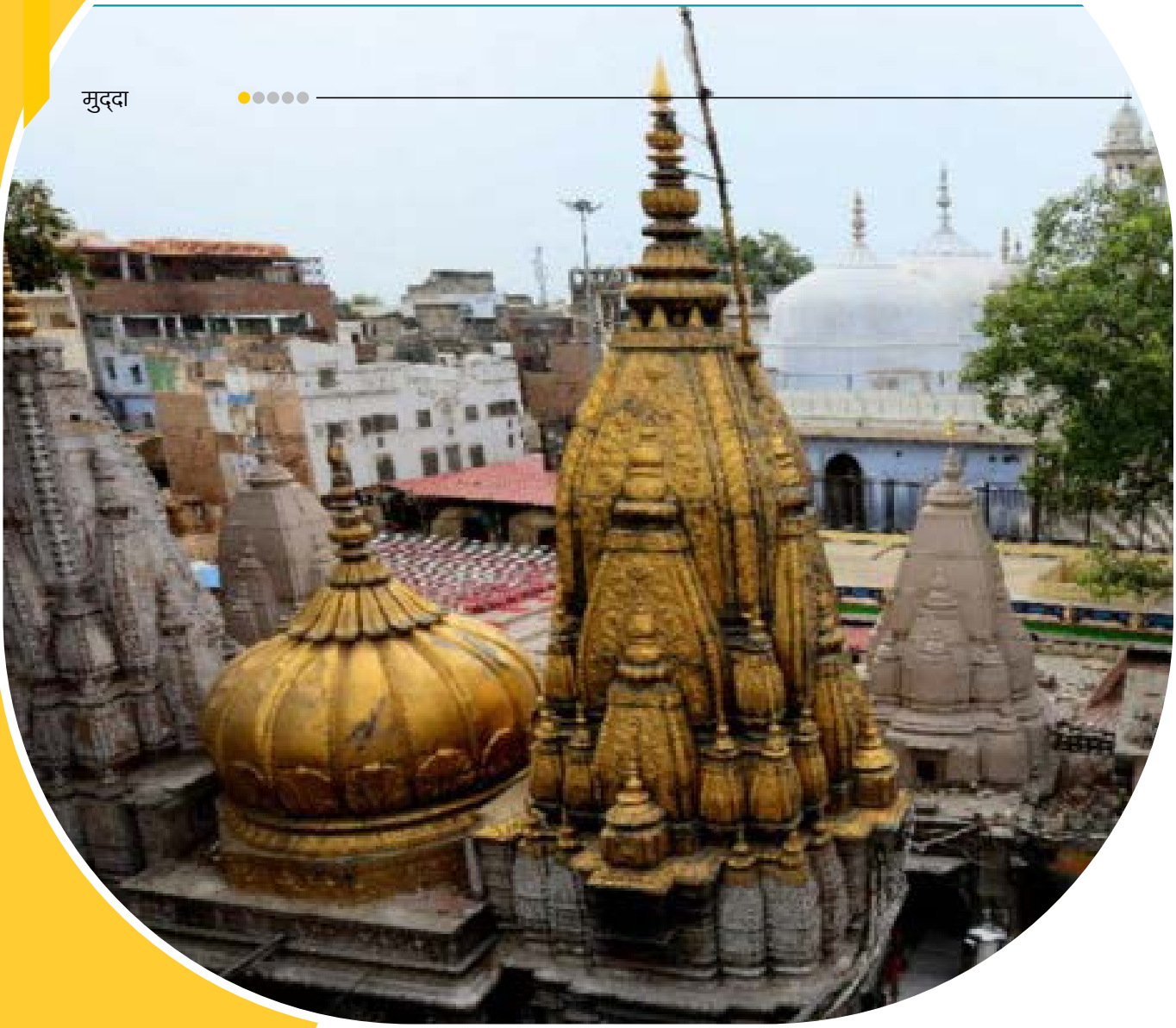

क्या है पूरा मामला?

हिंदू पक्ष का दावा है कि 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर को तुड़वा दिया था और वहां ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी. 1815 में अंग्रेजों ने इस जमीन को नीलाम कर दिया. इसे राजा पटनीमल ने खरीदा था. वो यहां मंदिर बनवाना चाहते थे. 1920 और 1930 के दशक में जमीन को लेकर विवाद हो गया. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अंग्रेजों ने जो जमीन बेची, उसमें कुछ हिस्सा ईदगाह मस्जिद का भी था.

क्या कहती है एक्ट की धारा-4?

जानकारों का कहना है कि इस याचिका में एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती दी गई है इसमें विशेष रूप से कानून के सेक्शन 4 का सब-सेक्शन 3 कहता है कि जो प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हैं उन पर ये कानून लागू नहीं होगा. मतलब अगर कोई जगह जिसका ऐतिहासिक महत्व है उसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं लाया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसे एंसियंट मॉन्यूमेंट एंड ऑर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट 1958 के तहत अपने संरक्षण में लेकर संरक्षित करेगा. ऐसे में इस तरह की जगहों को मंदिर मस्जिद की जगह ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर देखा जाएगा. अगर किसी बिल्डिंग को बने 100 साल हो गए हैं इसका कोई ऐतिहासिक महत्व है तो इसे एएसआई संरक्षित कर सकता है. इस नियम के हिसाब से कानून के कुछ जानकारों का मानना है कि मथुरा और काशी के मंदिरों के मामले इस कानून से बाहर हो जाते हैं.

हुआ था समझौता

बता दें कि 12 अक्तूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया. भारत के उद्योगपतियों के एक संघ जिसमें रामकृष्ण डालमिया, हनुमान प्रसाद पोद्दार और जुगल किशोर बिड़ला शामिल थे, ने जमीन खरीदी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का निर्माण करते हुए यहां भव्य केशवदेव मंदिर का निर्माण किया. तब समय के साथ ट्रस्ट ने पड़ोसी ईदगाह के साथ इस मुद्दे को सुलझा लिया गया और मस्जिद के हिस्से की जमीन ईदगाह को दे दी. पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है.

कर्नाटक में अब धर्म परिवर्तन करवाना होगा अपराध

धर्मांतरण विरोधी बिल से कांग्रेस हो गई नाराज

कर्नाटक विधानपरिषद में गुरुवार को धर्मांतरण विरोधी बिल को पारित कर दिया गया. कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयक को राज्य विधानसभा में पिछले साल दिसंबर में हरी झंडी मिल चुकी थी, लेकिन यह विधेयक अभी तक विधान परिषद में लंबित था.

अब विधान परिषद में इस विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही कर्नाटक देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है, जिनमें किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर सजा का प्रावधान है.

कांग्रेस ने किया सदन से वॉकआउट

विधान परिषद में सत्ताधारी भाजपा ने हंगामे के बीच इस बिल को पेश किया. प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया. विधान परिषद में बिल पेश होने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट ही कर दिया. इसके बावजूद भाजपा बिल को पारित कराने में सफल रही. कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज किया. उन्होंने कहा कि हम किसी की स्वतंत्रता पर निशाना नहीं साध रहे बल्कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए यह बिल लाए हैं.

दिसंबर में विधानसभा ने कर दिया था पास

मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की भाजपा सरकार ने कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयक को पिछले साल दिसंबर में विधानसभा में पेश किया था. विधानसभा में भी विपक्ष ने इस विधेयक का भारी विरोध

किया था और इसे कुछ समुदायों को निशाना बनाने की कोशिश बताया था. इसके बावजूद विधानसभा में विधेयक पारित हो गया था.

देश के 10 राज्यों में पहले से कानून, ओडिशा में 1967 से लागू

कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने वाला देश का 11वां राज्य है. सबसे पहले देश में ओडिशा में साल 1967 में ये कानून लागू किया गया था, जबकि हरियाणा (2022) इसे लागू करने वाला कर्नाटक से पहले आखिरी राज्य है.

इसके अलावा मध्य प्रदेश (1968), अरुणाचल प्रदेश (1978), छत्तीसगढ़ (2000), गुजरात (2003), हिमाचल प्रदेश (2006), झारखंड (2017), उत्तराखंड (2018) और उत्तर प्रदेश (2021) में भी यह कानून लागू है. गुजरात में साल 2003 में, छत्तीसगढ़ में साल 2006 में और हिमाचल प्रदेश में साल 2019 में इन कानूनों को संशोधित करते हुए और ज्यादा तीखा और कड़ा बनाया गया है. मध्य प्रदेश में साल 2020 में दोबारा अध्यादेश पेश किया गया, जिसे 2021 में मंजूरी देकर कानून बनाया गया.

तमिलनाडु और राजस्थान कदम बढ़ाकर हटे पीछे

तमिलनाडु और राजस्थान भी उन राज्यों में शामिल हैं, जहां धर्मांतरण कानून लागू करने की कोशिश की गई. तमिलनाडु ने 2002 में कानून लागू किया, लेकिन साल 2006 में ईसाई समुदाय के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद यह कानून वापस ले लिया गया. राजस्थान ने पहले 2006 और फिर 2008 में कानून बनाने के लिए विधेयक पारित किया, लेकिन सरकार को पहली बार राज्यपाल और दूसरी बार राष्ट्रपति से इस कानून को लागू करने की मंजूरी नहीं मिली. धर्मांतरण पर सख़्त हुई मोदी सरकार, NGO को विदेशी चंदा सबंधी नियमों में की गई कड़ाई

क्या कहता है कर्नाटक का धर्मांतरण कानून

इस कानून में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी अंतरण पर रोक लगाने का प्रावधान है. कानून को निम्न तरीके से समझा जा सकता हैः

1. विवाह के लिए धर्म परिवर्तन नहींः कानून के मुताबिक, धर्म परिवर्तन करने के लिए यदि कोई विवाह करता है तो उसे मंजूरी नहीं मिलेगी. साथ ही यदि किसी से जबरन विवाह करने के लिए कोई लड़के या लड़की का धर्मपरिवर्तन कराएगा तो वह भी गैरकानूनी माना जाएगा.
2. धर्म बदलना है तो पहले नोटिस दोः कानून में धर्म परिवर्तन करने की छूट भी दी गई है, लेकिन इसके लिए धर्म बदलने वालों को कम से कम एक महीना पहले जिला प्रशासन को नोटिस देकर सूचित करना होगा. नोटिस एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट या उससे ऊपरी रैंक के अधिकारी को ही देने पर मान्य होगा. इसके बाद धर्म परिवर्तन के उद्देश्य की जांच की जाएगी. जांच के बाद मंजूरी मिलने पर ही धर्म परिवर्तन संभव होगा.
3. किसकी शिकायत पर कार्रवाईः कानून की धारा-3 में जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध है. इसमें कहा गया है कि धारा-3 का उल्लंघन करने वाले धर्म परिवर्तन की शिकायत पीड़ित व्यक्ति कर सकता है. पीड़ित व्यक्ति के अलावा उसके माता-पिता, भाई-बहन या उससे ब्लड रिलेशन रखने वाले किसी रिश्तेदार की शिकायत पर भी ऋक्र दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
4. नहीं माने तो क्या होगी सजाः किसी नाबालिग, महिला या रउ/रळ व्यक्ति का धर्मांतरण जबरन करने या बिना इजाजत कराने पर सजा का प्रावधान है. ऐसे मामले में धर्म परिवर्तन कराने में दोषी माने गए हर व्यक्ति को तीन से दस साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही उन पर 1-1 लाख रुपये का जुमार्ना लग सकता है.
5. पीड़ित को मिलेगा 5 लाख का मुआवजाः जबरन धर्मांतरण साबित होने पर इससे पीड़ित होने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. साथ ही जुमार्ने की रकम भी उसे दी जाएगी. साथ ही ऐसे विवाह को फैमिली कोर्ट से अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. यदि जिले में फैमिली कोर्ट नहीं है तो पारिवारिक मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत को इसका अधिकार होगा.

जानें किस तरह मलेरिया की दवाई बेचने वाली कंपनी बन गई बोतलबंद पानी का बड़ा ब्रांड?

नई दिल्ली. बाजार में आज कई कंपनियां ऐसी हैं, जिनके नाम से उस प्रोडक्ट को जाना जाता है. अब उन प्रोडक्ट को सीधे कंपनी के नाम से खरीदा जाता है. इन नामों में एक नाम है बिसलेरी. अक्सर लोग बोतल बंद पीने का पानी खरीदने के लिए बिसलेरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं. हालत ये है कि अब बिसलेरी से मिलते-जुलते नामों की भी कई कंपनियां बाजार में आ गई हैं. वैसे बिसलेरी ने आज भले ही मार्केट का लंबा हिस्सा कब्जा रखा है, लेकिन इसकी शुरूआत काफी छोटी हुई थी.

इसके साथ ही जिस वक्त पानी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, तब लोगों का मानना था कि आखिर पानी खरीदकर कौन पिएगा और ये सिर्फ पैसे वालों तक ही सीमित रहेगा. हालांकि, अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं. ऐसे में जानते हैं कि आखिर बिसलेरी की क्या कहानी है और किस तरह से इटालियन व्यक्ति की शुरू की गई, कपंनी आज भारत में अच्छा बिजनेस कर रही हैङ्क

इटली के एक शख्स ने की थी शुरूआत

बिसलेरी की शुरूआत एक इटालियन बिजनेसमैन सिग्नोर फेलिस बिसलेरी ने की थी. इनका जन्म 20 नवंबर, 1851 को वेरोलानुओवा में हुआ था. पानी का काम शुरू करने से पहले बिसलेरी की शुरूआत दवाइयां बनाने के लिए की गई थी. इसके बाद 17 सितंबर, 1921 को फेलिस बिसलेरी का निधन हो गया था और उनके निधन के बाद उनके फैमिली डॉक्टर डॉ रॉसी इस कंपनी के मालिक बन गए. फिर डॉक्टर रॉसी के एक अच्छे दोस्त सन खुशरू सुनतूक भी उनके साथ जुड़े और उन्होंने भारत में बिसलेरी की स्थापना करने का काम किया. यह बात आजादी के कुछ दिन बाद की है और इस वक्त डॉ रॉसी ने साफ पानी बेचने का प्लान बनाया.

इसके बाद रॉसी का आइडिया 1965 में जमीन पर आया. फिर दोनों ने मुंबई के ठाणे में पहला 'बिसलेरी वाटर प्लांट' स्थापित किया था. लेकिन, उस दौरान लोगों ने इस बिजनेस प्लान का मजाक बनाया, क्योंकि वो पैसे लेकर बोतल में पानी बेचने पर काम कर रहे थे. लेकिन, उन्होंने अपना काम जारी रखा. फिर भारत के पैसे वालों के लिए बिसलेरी काफी फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि उन्हें उस वक्त में साफ पानी पीने को मिलने लगा. पैसे वाले लोगों ने तो बिसलेरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया था. हालांकि, उन्हें भी लगता था कि यह बिजनेस एक खास वर्ग तक सीमित रहेगा और उन्होंने इसे बेचने की सोची.

सोडा के लिए खरीदा मगर पानी बेचा

इस दौरान चार चौहान भाइयों के पारले समूह का बंटवारा भी हुआ था, जिसमें एक बेटे जयंतीलाल को सॉफ्ट ड्रिंक का कारोबार मिला. फिर उनके बेटे रमेश चौहान ने साल 1969 में बिसलेरी को इस मकसद से खरीद लिया कि इस ब्रांड को वे सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे. इसके बाद बिसलेरी के साथ ही उन्होंने कई प्रॉडक्ट लॉन्च किए, जिसमें कई पेय पदार्थ शामिल थे. मगर बाद में रमेश चौहान ने सॉफ्ट ड्रिंक का कारोबार तो कोका कोला को बेच दिया और पूरा ध्यान पानी बेचने पर लगाया.

इसके बाद कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही और आज ये कंपनी पानी बेचने के मामले में अग्रणी कंपनी है. अब कई कंपनियां इसके मिलते जुलते नामों से पानी बेच रही है और कंपनी लगातार प्रॉफिट के साथ अपना विस्तार करती जा रही है. बताया जाता है कि आज बिसलेरी भारत में सील्ड वाटर बोतल इंडस्ट्री में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखती है, जिसके पूरे देश में 135 वाटर प्लांट्स मौजूद हैं. इतना ही नहीं भारत में रोजाना 2 करोड़ लीटर से ज्यादा पीने का पानी बिसलेरी के जरिए बिक जाता है.

> घरों में चूहों का होना मतलब बीमारियों और परेशानियों का होना. चूहें घरों में आकर सारा सामान बर्बाद कर देते हैं. फिर चाहे वो खाने का हो या पहनने के कपड़े हो.

क्या आपके घर में भी चूहों ने मचा दी है तबाही

तो आज ही करें इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल

अपना घर सभी को प्यारा होता है. घर छोटा हो या फिर बड़ा घरों की साफ-सफाई रखना बेहद जरूरी होता है. लेकिन क्या हो जब आपके ही घर में बिन बुलाए मेहमान आकर रहना शुरू कर दें. घबराई मत हम किसी इंसान की नहीं बल्कि उन चूहों की बात कर रहे हैं, जो घर में आने के बाद फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं. पूरे घर में ईधर से उधर और उधर से ईधर घूमते ही रहते हैं. जगह-जगह गंदगी फैलाते हैं.

घरों में चूहों का होना मतलब बीमारियों और परेशानियों का होना. चूहें घरों में आकर सारा सामान बर्बाद कर देते हैं. फिर चाहे वो खाने का हो या पहनने के कपड़े हो. लेकिन अब आप चूहों को घर से भगा सकते हैं, वो भी महज कुछ आसान उपाय के जरिए.

नेप्थलीन बॉल्स से भगाएं चूहें

- चूहों को नेप्थलीन बॉल्स की महक जरा भी पसंद नहीं होती है.
- किचन, बाथरूम और स्टोर रूम के अंदर नेप्थलीन बॉल्स रख दें.
- नेप्थलीन बॉल्स को फोड़कर पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
- पाउडर को आटे के साथ गूंथकर भी कर के कोने-कोने में लगा सकते हैं.
- नेप्थलीन के पाउडर को चावल में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
- बेकिंग सोडा या पेपरमिंट से भगाएं चूहें
- बेकिंग सोडा या पेपरमिंट के इस्तेमाल से चूहों को घर से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है.
- सबसे पहले एक कप आटे को अच्छे से गूंथ लें. फिर इसमें बेकिंग सोडा या पेपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदों मिलाकर फिर से गूंथे.
- आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर घर के उन स्थानों पर रख दें जहां चूहे सबसे अधिक लगते हैं.

दुनिया में मंदी का खौफ

भारत के 17 अरबपतियों ने गंवाए 71 हजार करोड़ रुपये

वर्ल्ड बैंक (World BÔ»»fk) के साथ कई आर्थिक एजेंसियां अगले साल तक दुनिया के मंदी में जाने का अनुमान जता चुकी है. जिसकी वजह से दुनियाभर के बाजार के साथ भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में करीब दो फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. जिसका असर देश के 18 में से 17 अरबपतियों की दौलत पर देखने को मिला है. आंकड़ों के अनुसार देश के 17 अरबपतियों की कुल संपत्ति से 71 हजार करोड़ रुपये साफ हो गए. आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में...

17 अरबपतियों की नेटवर्थ को 71 हजार करोड़ रुपये का नुकसान

ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों अनुसार भारत में कुल अरबपतियों की संख्या 18 रह गई है. जिनमें से अंबानी और अडानी समेत 17 अरबपतियों की नेटवर्थ में से 8.9 अरब डॉलर यानी 71 हजार करोड़ रुपये कम हो गए हैं. वैसे तो दुनिया के तमाम अरबपतियों की नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली है, इसमें सिर्फ भारतीय अरबपतियों का डाटा ही ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स से संकलित है. दुनिया के बाकी अरबपतियों की नेटवर्थ में तो लगातार ही गिरावट देखने को मिल रही है.

किस भारतीय अरबपति को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

हाल ही में जिन भारतीय अरबपतियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, उनमें अंबानी और अडानी का नाम सबसे आगे है. दोनों ही अरबपतियों की नेटवर्थ से दो अरब डॉलर से ज्यादा कम हुए हैं. मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से 2.31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसके बाद उनकी कुल नेटवर्थ 88.7 अरब डॉलर रह गई है और वो दुनिया के 10वें सबसे अमीर अरबपति के पायदान पर आ गए हैं. वहीं दूसरी ओर गौतम अडानी की नेटवर्थ में से 2.12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. जिसके बाद उनकी कुल नेटवर्थ 147 अरब डॉलर हो गई है. अब वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं. मंदी के खौफ से सहम गया Stock MÔrket, निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डूबे

देश के किस अरबपति को हुआ कितना नुकसान

अरबपति का नाम	नुकसान (बिलियन डॉलर में)
गौतम अडानी	2.12
मुकेश अंबानी	2.32
अजीम प्रेमजी	0.757
शिव नाडर	0.483
राधाकिशन दमानी	0.977
उदय कोटक	0.033
दीलिप शांघवी	0.116
सावित्रि जिंदल	0.251
सुनील मित्तल	0.097
साइरस पूनावाला	0.141
कुमार बिड़ला	0.437
केपी सिंह	0.515
अश्विन दानी	0.155
नुस्ली वाडिया	0.158
बेनू बांगर	0.172
विक्रम लाल	0.127
महेंद्र चोकसी	0.143

बाढ़ और सूखा प्रकृति का हिस्सा हैं लेकिन पिछले दो दशकों से शहरों में क्यों मच रही तबाही?

नई दिल्ली. भारत में इस समय बाढ़ से कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना पस्त है. हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में घरों में पानी घुस आया है और उससे बचने के लिए लोगों को होटलों का सहारा लेना पड़ रहा है. होटलों में एक रात बिताने का चार्ज 40 हजार रुपये तक वसूल रहे हैं. ऐसी ही कमोबेश कहानियां पाकिस्तान से सुनने में आ रही हैं.

बाढ़ की त्रासदी एक ओर लोगों को पस्त कर रही जबकि उन्हीं इलाकों के लोग इस विपरीत परिस्थिति में मदद करने की बजाय लूट में लग गए हैं. 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ के चलते आई भयंकर त्रासदी के दौरान भी बुनियादी चीजों मसलन दूध और अंडों के दाम कई गुणा ज्यादा वसूले गए थे. अब सवाल है कि बाढ़ किन वजहों से आती है? क्या बाढ़ आने और उसकी त्रासदी बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच जाने की वजह हमारा लालच है? हमें अन्य सवालों पर बात करने से पहले यह समझना होगा कि बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही प्रकृति का हिस्सा हैं पर यह त्रासदी क्यों बन जाती है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाढ़ क्यों आती है?

बाढ़ क्यों आती है?

पानी के संग्रह होने के जितने भी प्राकृति स्रोत हैं मसलन नदी, समुद्र, ताल, तलैया, झील, नहर, पोखर, नाले आदि जब ओवरफ्लो होने लगे और पानी मैदानी या समतल इलाकों की ओर बहने लगे तो हम उसे बाढ़ कहते हैं. भारत मूल रूप से धनजल यानि अधिक जल वाला देश है. देश के कुछ इलाकों या प्रदेशों को छोड दें

शहरों में घुस रहा है बाढ़ का पानी

हालांकि, पिछले दो-तीन दशकों में ग्लोबल वार्मिंग और शहरों के बढ़ते दायरे और कंक्रीट के जंगलों के चलते बाढ़ के चलते जानमाल की हानि ज्यादा होने लगी है. बाढ़ पहले नदियों के किनारे बसे गांवों को कुछ दिनों तक डुबोकर वापस चली जाती थी लेकिन दो दशकों में बाढ़ शहरों में अपने पांव पसारने लगी है. कभी मुंबई डूबने लगता है तो कभी अहमदाबाद और कभी बेंगलुरु.

नदियां बाढ़ को समुद्र तक ले जाती हैं

यह एक तथ्य है कि नदियां पहाड़ों से निकलकर समतल इलाकों से बहती हुई समुद्र में जाकर गिरती थीं लेकिन बड़े पैमाने पर नदियां मर चुकी हैं. यही कारण है नदियां अब बाढ़ का पानी समुद्र तक ले जाने में असमर्थ हो रही हैं. दूसरा तथ्य यह है कि समुद्र का पानी मैदानी इलाकों में घुसने से नदियां रोकने का काम भी करती थीं. इन दो घटनाओं के चलते बाढ़ की त्रासदी में लगातार इजाफा हो रहा है.

तो ज्यादातर राज्यों में अच्छी बारिश होती है और सबसे मजेदार बात यह है कि हम भारतीय इसके साथ जीने-मरने के आदी हो चुके हैं.

भारत में मल्टीलेन वाली सड़कों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है. इस काम को अंजाम देने के लिए एक ओर पेड़ काटे गए तो दूसरी ओर पानी के निकलने या जमा होने के रास्तों को बंद किया गया है. जाहिर सी बात है कि आसमान से गिरने वाली बूंदों को अब इकट्ठा होने और ताल-तलैयों तक पहुंचने के काम में बाधा पहुंचाई गई है. प्रकृति बहुत लंबे समय में अपनी सभी चीजों का निर्माण करती है. प्रकृति निर्माण में कोई तय समय में या किसी खास समय के कैलेंडर में चीजें नहीं बनाती है लेकिन मनुष्य विकास के नाम पर अपनी चीजें बनाने में कम से कम समय लेता है. हमें इस तरह की हेडलाइन बहुत आकर्षित भी करती है- सबसे कम समय में दुनिया के सबसे बड़े पुल का निर्माण, सिर्फ 2 साल में इस नदी पर बना एशिया का सबसे बड़ा बांध आदि. दरअसल, प्रकृति तब भयंकर रूप लेती है जब हमारी मुनाफाखोरी प्रवृत्ति उसके साथ सामंजस्य बिठाने की बजाए हम उसे नोंचने, खसोंटने, छीलने, चीरने में लग जाते हैं. जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान आखिरकार मानव सभ्यता को ही चुकानी पड़ती है.

मानसून के बाद चक्रवात बाढ़ की त्रासदी बढ़ाती है

साइंस डारेक्ट डॉटकॉम नाम की एक वेबसाइट के अनुसार, वर्ष 2021 में एक अध्ययन कराया गया था जिसमें यह कहा गया था कि पिछले 50 वर्षों में भारत में मौसम से संबंधित होने वाली मौतों में से 75 फीसदी मौत बाढ़ और चक्रवात के चलते होती है. एक अध्ययन में यह बताया गया है कि मानसून के ठीक बाद चक्रवात आने से बाढ़ की त्रासदी कई गुणा बढ़ जाती है. अगस्त 2018 में केरल की बाढ़, दिसंबर 2015 में चेन्नई की बाढ़, जून 2013 में उत्तराखंड की बाढ़, जून 2010 में लेह की बाढ़ और 2005 में मुंबई की बाढ़ की वजह चक्रवात ही थी. चक्रवात के चलते होने वाली पानी ज्यादा गिरता है जबकि शहरों के दायरे बढ़ने और गांवों में हर जगह पक्की सतह बनने से पानी के निकलने के रास्ते बहुत कम रह गए. शहरों में ताल-तलैयों में मिट्टी भरकर वहां बिल्डिंगें खड़ी कर दी गईं. दिल्ली में आजादी के समय 350 से ज्यादा तालाब थे लेकिन आज शायद चार भी तालाब अच्छी हालात में नहीं रह गए.

पहले मां दुर्गा की झांकियां सजाई जाती हैं. खास बात यह है यहां मुस्लिम कारीगर मां दुर्गा की झांकी के लिए जरूरी पोशाक और गहनों से लेकर ढांचा तैयार करने तक सभी काम बखूबी और श्रद्धा से करते हैं. कटक में यह परंपरा मुस्लिम कारीगरों द्वारा वर्षों से चली आ रही है.

ओडिशा में नवरात्रि से पहले मुस्लिम कारीगर तैयार करते हैं मां दुर्गा की झांकी

वर्षों से चली आ रही परंपरा

कटक के बांका बाजार में रहने वाले मुस्लिम कारीगर पीढ़ियों से मां दुर्गा की झांकियां तैयार करते आ रहे हैं. मुस्लिम कारीगर खुशी-खुशी श्रद्धा के साथ काम को बखूबी करते हैं और इसके जरिये सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देते हैं. उन्हें इस काम के लिए पड़ोसी राज्यों से भी बुलावा आता है.

Muslim Artist

झांकी में मां दुर्गा की मूर्ति के लिए गहने-पोशाक आदि का काम मुस्लिम कारीगरों द्वारा खुशी से किया जाता है. बड़ी संख्या में मुस्लिम करीगार जरी का काम करते हैं. साथ ही साथ झांकी का ढांचा तैयार करते हैं. मां दुर्गा का एक झांकी तैयार करने में सैकड़ों कारीगर एक साथ काम करते हैं. आखिर में मां दुर्गा की भव्य झांकी तैयार होती है जिसका दर्शन कर श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं. आजतक से बातचीत में कारीगर सैयद असलम ने कहा कि हम सभी एक कारीगर हैं और करीगर सभी धर्मों का सम्मान करता है. हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से मां दुर्गा की झांकी बनाने का कार्य किया है. हम सभी मां दुर्गा की झांकी बनाकर अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. मां दुर्गा की झांकी को तैयार करने के लिए बड़ी संख्या में कारीगरों का योगदान होता है.

Muslim Artist

असलम ने विस्तार से कहा कि नवरात्र शुरू होने से पहले ही बड़े पैमाने पर मुस्लिम कारीगर मां दुर्गा की झांकियां बनाना आरंभ कर देते हैं. इस दौरान कारीगर माता की पोशाक और गहनों से लेकर ढांचा तैयार करने तक सभी काम बखूबी और खुशी-खुशी करते हैं. आखिर में नवरात्रा के सप्तमी से पहले मां दुर्गा की भव्य झांकी तैयार होती हैं जिसका दर्शन कर श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं. मां दुर्गा की झांकी बनाने के लिए हमें अन्य पड़ोसी राज्यों से बुलावा आता है. साथ ही अपने इस कार्य के जरिये सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देते हैं.

52 वां शक्तिपीठ माना जाता है दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर

छह भुजाओं वाली है बस्तर की मां तारणी

मान्यता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस जगह देवी सती के दांत गिरे थे, उसी इलाके का नाम दंतेवाड़ा पड़ा. यहां पर देवी मां का प्राचीन मंदिर है. वैसे तो देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का ही जिक्र है, लेकिन कुछ स्थानीय मान्यताएं अलग कहानी बयां करती हैं. इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता मंदिर को 52वां शक्तिपीठ माना जाता है. इस मंदिर को लेकर कई तरह की कहानियां और किवदंतियां प्रसिद्ध हैं. आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण 14वीं सदी में चालुक्य राजाओं ने दक्षिण भारतीय वास्तुकला से कराया था. यहां देवी मां की षष्टभुजी काले रंग की मूर्ति स्थापित है. छह भुजाओं में देवी ने दाएं हाथ में शंख, खड्ग, त्रिशूल और बांए हाथ में घंटी, पद्म और राक्षस का धड़ लिया हुआ है. मंदिर में देवी के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं.

मशहूर है लोक कथा

एक लोककथा के मुताबिक प्राचीन भारत के राज्य वारंगल के राजा प्रतापरुद्रदेव थे. जब उनके छोटे भाई अन्ममदेव को वारंगल से निर्वासित कर दिया गया तो वह दुखी मन से गोदावरी नदी को पार कर रहे थे. उसी दौरान उन्हें नदी में मां दंतेश्वरी की प्रतिमा मिली. अन्ममदेव उस प्रतिमा को उठाकर नदी के किनारे लाए और उसकी पूजा करने लगे. तभी माता दंतेश्वरी ने साक्षात प्रकट होकर अन्ममदेव से कहा कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे चलूंगी. कहा जाता कि माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से अन्ममदेव ने अपने रास्ते पर चलते हुए कई राज्य जीते. दंतेवाड़ा में जिस जगह वह जाकर रुके वहां माता स्थापित हो गईं. इस प्रकार उन्होंने बस्तर साम्राज्य की स्थापना भी की. इतिहास में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि बारसुर के युद्ध में राजा अन्मदेव ने हरिशचंद्र देव को मारकर बस्तर में अपने राज्य की स्थापना की थी.

52वां शक्तिपीठ है दंतेवाड़ा

माता दंतेश्वरी के मंदिर को 52वां शक्तिपीठ माना जाता है. कहते है कि डंकिनी और शंखिनी नदी के संगम पर बने इस मंदिर का जीर्णोद्धार पहली दफा वारंगल के पांडव अर्जुन कुल के राजाओं ने लगभग 700 साल पहले करवाया था. बताया जाता है कि वर्ष 1883 तक इस मंदिर में नरबलि भी होती थी. साल 1932-33 में दंतेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार दूसरी बार किया गया, जो उस समय की बस्तर महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने कराया था.

तांत्रिकों की साधना स्थली है दंतेवाड़ा

यह मंदिर शंखिनी और डंकिनी नदी के संगम पर स्थित है. स्थानीय लोग बताते हैं कि नदी तट पर आठ भैरव भाइयों का आवास है, इसलिए इस स्थान को तांत्रिकों की भी साधना स्थली भी माना जाता है. मान्यता है कि आज भी इस जगह पर गुप्त रूप से बहुत से तांत्रिक जंगलों की गुफाओं में तंत्र विद्या की साधना में लीन हैं. मंदिर प्रांगण में नलयुग से लेकर छिंदक नाग वंशीयकाल की कई मूर्तियां बिखरी हुई हैं. माता दंतेश्वरी को बस्तरराज परिवार अपनी कुल देवी मानता है, लेकिन वह पूरे बस्तरवासियों की रक्षक हैं.

6 महीने के निचले स्तर पर सोने का भाव

क्या यही है खरीदने का सही समय?

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद फरवरी 2022 के अंत से भारत में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. डॉलर इंडेक्स 20 साल के अपने सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 81 रुपये के करीब पहुंच गया है.

मजबूत होते डॉलर इंडेक्स और भारतीय करेंसी में लगातार गिरावट के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई. टउ पर गोल्ड का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अपने छह महीने के निचले स्तर को छूने के बाद 49,399 प्रति 10 ग्राम पर इस सप्ताह क्लोज हुआ. टउ पर सोने की कीमत 49,250 रुपये प्रति 10 ग्राम तक नीचे गिर गई थीं, जो पिछले छह महीने की सबसे लो लेवल है.

जारी रह सकती है गिरावट

सोने का हाजिर भाव 1,639 डॉलर प्रति औंस के इंट्रा डे लो पर पहुंचने के बाद 2 साल के निचले स्तर 1,643 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ. कमोडिटी मार्केट के जानकारों के अनुसार, सोने की कीमत में गिरावट लंबे समय तक जारी रह सकती है. क्योंकि वैश्विक मंदी, महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट की वजह से गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है.

कितनी कम हो सकती है कीमतें

मार्केट के एक्सपर्ट्स के अनुसार, मजबूत डॉलर और बढ़ी हुई यूएस बांड यील्ड के चलते निवेशकों का रुझान कम हुआ है. डॉलर इंडेक्स 20 साल के अपने सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है. गोल्ड की कीमतें दो साल निचले स्तर पर आ गई हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स निवेशकों को थोड़ा और इंतजार खरीदने की सलाह दी रहे हैं. उनका मानना है कि घरेलू बाजार में सोना 48,000 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच सकता है.

फरवरी के बाद से गिरावट

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद फरवरी 2022 के अंत से भारत में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. फरवरी के अंत में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था. फिलहाल यह 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है. जियो-पॉलिटिकल कारणों से बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, अक्षय तृतीया के समय अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत में सोने की मांग में 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.

रुपये में बड़ी गिरावट

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 81 रुपये के करीब पहुंच गया है. पिछले कुछ महीनों में रुपये की कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. इसे लेकर अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं. शुक्रवार को 83 पैसे की गिरावट हुई, जिसे पिछले सात महीने में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट मानी गई है.

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स से मिल रही 12 तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं

रायपुर. स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतरता और इसे अधिक सुगम बनाने के लिए प्रदेश भर में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए गए हैं. लोगों तक सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इन सेंटर्स में 2667 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (उल्ड) भी नियुक्त किए गए हैं. इन केंद्रों में प्रसव पूर्व देखभाल व प्रसव, नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं संचारी रोग व गैर-संचारी रोग स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, सामान्य रोगों के लिए बा' रोगी देखभाल एवं प्रबंधन, आंख-नाक-कान-गला संबंधी सामान्य देखभाल, मुख स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, वयोवृद्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जैसी 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं. लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए इन केंद्रों के माध्यम से योग एवं वेलनेस की गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं.

स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक एवं हेल्थ एन्ड वेलनेस सेंटर्स के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. सुरेंद्र पामभोई ने बताया कि प्रदेश के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स में टेली-मेडिसीन के माध्यम से चिकित्सकों द्वारा मरीजों को विशेषज्ञ स्तर की सलाह व परामर्श प्रदान की की जा रही है. ई-संजीवनी टेली-मेडिसीन सेवा के माध्यम से अब तक कुल चार लाख 43 हजार मरीजों को प्राथमिक स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने बताया कि 6 जून 2022 से 11 जून 2022 तक प्रदेश के सभी जिलो में टेली-मेडीसिन सप्ताह का आयोजन कर एक लाख 63 हजार 244 टेली-कंसल्टेशन किया गया. इसमें 3680 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स ने अपनी सहभागिता दी थी. भारत सरकार के नीति आयोग ने भी इसको सराहा था. वर्ष 2021 में कोण्डागांव जिले के खल्लारी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर की टीम को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल दिवस पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया जा चुका है. डॉ. पामभोई ने बताया कि कोरोना महामारी काल में भी गंभीर एवं गैर-संक्रामक रोग से ग्रसित मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं को घर पहुंचकर दवाईयां हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्रदान की गईं. इस दौरान डायबिटीज (मधुमेह) के कुल एक लाख 99 हजार 345, उच्च रक्तचाप के एक लाख 33 हजार 452, टी.बी. के 6245 और कुष्ठ के 2845 मरीजों को दवाईयां मुहैया कराई गईं. एक लाख 96 हजार 235 गर्भवती महिलाओं को भी इस दौरान दवाईयां वितरित की गईं. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले 30 साल से अधिक उम्र के लोगों के रक्तचाप, डायबिटीज व कैंसर जैसी बीमारियों की निःशुल्क जांच की जाती है. इनके मरीजों को जरूरत के अनुसार निःशुल्क दवा और परामर्श भी दिया जाता है. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में उपचार के साथ-साथ लोगों को स्वस्थ जीवन-शैली के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

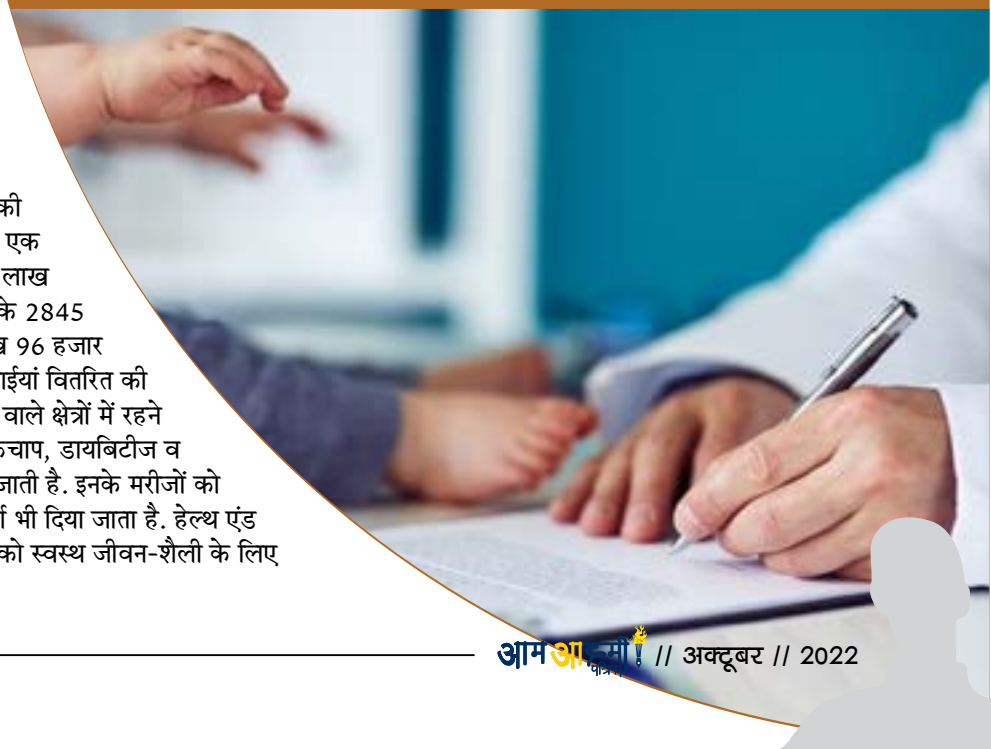

ये 4 बातें पति-पत्नी के रिश्ते को कर देती हैं खोखला

जिंदगी बर्बाद होने से पहले जान लें

पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार ही काफी नहीं होता है, बल्कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिनके न होने पर आप शादी करने का अफसोस महसूस करते हैं. आप अपने पार्टनर पर कितना भी भरोसा क्यों न करते हों, लेकिन अगर आप छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपके रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता है.

इस बात में कोई दोराय नहीं है कि एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का काम प्यार, विश्वास और आपकी समझदारी ही करती है. हालांकि शादी के बाद सिर्फ यही बातें काम नहीं आती, बल्कि कई छोटी-छोटी चीजों का भी ध्यान रखना होता है. कई ऐसी बातें होती हैं, जिन्हें बर्दाश्त कर पाना बस की बात नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए. छोटी-मोटी लड़ाई होना पति-पत्नी के बीच आम बात है, लेकिन हर दिन ऐसा होने पर आपको सतर्क होने की जरूरत है. अगर आपका शादीशुदा समझौते, इमोशनल अब्यूज से जूझ रहा है, तो आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए. हस्बैंड-वाइफ के बीच इस तरह की चीजें हर दिन होने के बाद रिश्ता कमजोर होने लगता है. ऐसे में कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिन्हें देखने के बाद अगर समय पर फैसला नहीं लिया जाए, तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

कड़वे शब्दों का प्रयोग करना

ऐसा कहा जाता है कि जितना आप किसी को सामने से वार करके नहीं हर्ट कर सकते, उससे कहीं ज्यादा अपने तीखे शब्दों के बाण चलाकर कर सकते हैं. शादी के बाद अगर आप इमोशनली कमजोर पड़ने के कारण उसमें रहने को मजबूर हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. प्यार करने के बाद आपको और आपके पार्टनर को एक-दूसरे की खामियों के साथ स्वीकार करना

लोगों से बात करने के लिए मना करना

अगर आपका पार्टनर आपको आपकी सोशल लाइफ खत्म करने को कहता है, तो सावधान हो जाएं. कोई भी सही पार्टनर आपकी शादी के बाद आपकी जिंदगी पर रोक-टोक नहीं लगाएगा. लेकिन अगर वह आपको हर वक्त घर पर रहने को कहता है या ऑफिस से सीधे घर आने पर फोर्स करता है, तो आपको एलर्ट होने की जरूरत है. ऐसे में भले ही आपका पार्टनर आपको कोई भी रीजन देने की कोशिश करें, लेकिन आपको इस पर गंभीरता से विचार करने की जररूत है. वैसे भी इस तरह के रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं. एक न एक दिन यह टूट ही जाएगा.

होता है, लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपका अपमान करना साथी बर्दाश्त नहीं कर पाता है. आप मानसिक तौर पर टॉर्चर होने लगते हैं. आपकी इस तरह की आदत आपकी मैरिड लाइफ को तबाह करने में देर नहीं लगाती है.

समझौते से जब भर जाती है जिंदगी

अगर एक शादीशुदा रिश्ते में सिर्फ एक ही पार्टनर को हर बार समझौता करना पड़ता है, तो वह भले ही कुछ कहे न, लेकिन आपसे दूर होता चला जाता है. जब आप कोई भी प्लान बनाने के बाद खुद ही उसे कैंसिल करने लगते हैं और पार्टनर को समझने की बात कहते हैं, तो वे आपके साथ बोर फील करने लगते हैं. आप अपनी सुविधा अनुसार हर काम न करें, वरना आपका रिश्ता टूटने में भी देर नहीं लगती. यहां एक पार्टनर को यह महसूस होने लगता है कि हर बार वह ही कॉमप्रोमाइज करने पर मजबूर रहता है. इसका बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि वह खुद ही रिश्ते से निकलने की ढान लेता है.

लड़ाई में नीचा दिखाना शुरू कर देना

आपकी साथी से किसी भी बात पर बहस हो, लेकिन उसे नीचा दिखाना आपकी रिस्पेक्ट को भी उनकी नजर में कम कर देता है. लेकिन कई बार पति-पत्नी लड़ाई में यह भूल जाते हैं और एक-दूसरे को अपशब्दों से लेकर कई गलत बातें बोल जाते हैं. जो न सिर्फ रिश्ते को खत्म कर देती हैं बल्कि आपके दिल में पार्टनर के लिए नफरत भी भर देती है. वहीं लड़ाई में आप कई बार रिश्ता खत्म करने की बात कहने लगते हैं, जो साथी को इस बात का भी एहसास कराता है कि आप उन्हें कभी भी छोड़ सकते हैं. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी शादी हो चुकी है और आपका चीखना-चिल्लाना आपके रिश्ते को कमजोर करने के सिवाए कुछ और नहीं करेगा.

माह : अक्टूबर 2022

राशिफल

मेष

सितंबर का यह माह आपके लिए मिलेजुले प्रभाव लेकर आ रहा है. आर्थिक स्थिति मध्यम रहेंगी. कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी पूर्व में अटके कई काम सुचारु रुप से शुरू होंगे. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों लाभ प्राप्त होगा. किंतु काम का बोझ महसूस करेंगे.टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों सावधानी बरतने की आवश्यकता है' छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा के लाभ प्राप्त होगा. व्यापारी वर्ग पैसे के लेनदेन को लेकर सावधानी बरतें अन्यथा पैसा अटक सकता है.

वृष

सितंबर का यह माह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी धनलाभ के योग बनेंगे. कार्यक्षेत्र में चल रहे तनाव दूर होंगे. आर्थिक योजना पर पूंजी निवेश करेंगे. व्यापारिक मामला आपके पक्ष में रहेंगे. क्रोध की अधिकता रह सकती है संयम धारण करें. कलात्मक एवं रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल रहेगा समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी .

मिथुन

सितंबर का माह आप के लिए अनुकूल समय ले कर आ रहा है. धन से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होगा. आर्थिक उन्नति होगी. कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी उच्च अधिकारों का सहयोग प्राप्त होगा. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को पद प्रमोशन की प्राप्ति होगी. व्यापार में चले आ रहे गतिरोध दूर होंगे धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे. जमीन, घर, वाहन आदि खरीदने के योग बन रहे हैं. प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल है.

कर्क

सितंबर का यह माह आपके लिए मिलाजुला फल लेकर आ रहा है. धन की स्थिति बेहतर रहे गी. कार्यक्षेत्र में चली आ रही परेशानियां दूर हो गी. बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी. उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को पद प्रमोशन इन्क्रीमेंट आदि मिल सकता है .पत्रकारिता एवं मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन रहेगा.

सिंह

सितंबर का यह माह आप के लिए अनुकूल रहेगा. पूर्व में चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी. कार्यक्षेत्र में सभी रुकें हुए कार्यों सुचारु रुप से चलेंगे एवं मान सम्मान में वृद्धि होगी. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि मिलने के योग हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपके पक्ष में रहेंगे.

कन्या

सितंबर का यह माह आपके लिए बेहतरीन साबित होगा. आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है. व्यापार में उन्नति होगी धन लाभ के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा कायम होगा. उच्चाधिकारी को प्रशंसा के पात्र बनेंगे.पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद रह सकता है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उभर सकती है खानपान में सावधानी बरतें. सुख सुविधा के सामान को लेकर अधिक व्यय होंगे.

तुला

सितंबर का यह माह आप के लिए परेशानी भरा रह सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेंगी. कार्यक्षेत्र में बाधाएं रह सकती है. काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान का अनुभव करेंगे.सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाकर चले.आर्थिक निवेश को लेकर सावधानी बरतें. व्यापारिक मामले बंद गति से चल सकते हैं पैसे की लेनदेन को लेकर सावधानी वरते. छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी.

वृश्चिक

सितंबर का यह माह आपके लिए सामान्य से बेहतर साबित होगा. आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेंगे. धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी. कार्यक्षेत्र में पूर्व में अटके सभी कार्य सुचारु रुप से चलेंगे. सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. क्रोध की अधिकता के चलते किसी उलझन में पड़ सकते हैं बेवजह किसी बहस में न पड़े.सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को प्रमोशन आदि मिल सकता है. कोट कचहरी से जुड़े मामले अपने पक्ष में रहे गे .

धनु

सितंबर का यह माह आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा. आर्थिक उन्नति होगी. धन लाभ के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र से जुड़े सभी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक योजनाओं पर पूंजी निवेश करेंगे जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होंगे. बेरोजगारों को नए रोजगार प्राप्त होंगे.

मकर

सितंबर का यह माह आपके लिए मिलाजुला प्रभाव लेकर आ रहा है. आर्थिक स्थिति बेहतर रहे गी किंतु मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं. शरीर में आलस्य का प्रभाव रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बरतें. कार्यक्षेत्र में भी मिले जुले प्रभाव रहेंगे काम काजी मामले मंद गति से चलेंगे. पूंजी निवेश को लेकर सावधानी बरतें. व्यापारिक मामले अटक सकते हैं धैर्य से काम लें.भाग्य का सहारा मिलेंगे सभी कार्य मंद गति से पूर्ण होंगे.

कुम्भ

सितंबर का यह माह आपके लिए कठिनाई भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में बनते काम बिगड़ सकते हैं. उच्चाधिकारियों के क्रोध का भाजन बन सकते हैं. समय पर कार्य पूरा करना चुनौतीपूर्ण रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेंगी.बहुत अधिक मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होगी. व्यापार में पूंजी निवेश सोच समझकर करें. पत्रकारिता एवं मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है.

मीन

सितंबर का यह माह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में सामना करना पड़ सकता है किंतु फिर भी सफलता प्राप्त होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे.व्यापारिक मामला आपके पक्ष में रहेंगे कोई बड़ा अनुबंध हाथ लग सकता है. धन लाभ के योग बन रहे हैं.ब्रोकिंग, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन साबित होगा.